कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र., भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 845 / 2022 / 10–11 / 2855 भोपाल, दिनांक 30/05/2024

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः– **वन मंडल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न, माड़ा, पूर्व सरई के विभिन्न RF वन कक्षों के रकबा 1335.35 हे. वनभूमि तथा विभिन्न खसरों के रकबा 62.19 हे. राजस्व वनभूमि कुल 1397.54 हे. वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक अन्तर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा उपरी सतह उपयोग के प्रत्यावर्तन का मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्से प्रा.लि.. का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/142344/2021/**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का दिनांक 02 / 02 / 2024 एवे 15 / 05 / 2024

---0---

कृपया आपके संदर्भित पत्रो दिनांक 02 / 02 / 2024 एवे 15 / 05 / 2024 से विषयांकित परियोजना के सम्बन्ध में 15 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है ।

अतः 15 बिन्दुओं मे से कुछ बिन्दु आवेदक संस्था से संबंधित है तथा कुछ बिन्दुओं का संबंध वन विभाग से हैं। आवेदक संस्था से संबंधित बिन्दुओं की जानकारी उनके द्वारा प्रस्ताव के भाग–1 में अतिरिक्त जानकारी के बिन्दु क्रमांक–41 पर अपलोड कर दी गई है, जिसका अवलोकन पोर्टल पर किया जा सकता है। शेष बिन्दुओं की जानकारी क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त की गई।

आपके द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

i. Calculated area of Shape file/ KML file of Forest land proposed for diversionwithin the mining lease is found 1601.058 Ha (software calculated). However, instant proposal has been submitted for diversion of 1397.54 ha forest land only.

इस शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माईनिंग लीज का क्षेत्रफल रकबा 2672.00 हेक्टेयर है जिसमें से 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि है तथा शेष 1274.46 हेक्टेयर अन्य गैरवनभूमि का क्षेत्रफल है। सुधारोपरान्त प्रस्तावित वनक्षेत्र रकबा 1397.54 हेक्टेयर की KML File ऑनलाइन प्रस्ताव के भाग–1 में अपलोड की गई है।

ii. The Sanjay Dubri Wildlife Sancturary is located at a distance of 10.7 Km from the proposed forest land for diversion. Moreover the State Govt. informed that the proposed area is falling within the 1 km of the elephant corridor as per the prevailing working plan for the period 2019-20 to 2028-29. Further, movement of leopard (Tendua) reported in the SIR of the DFO, Singrauli. Therefore, the comments from CWLW along with proposed mitigation measures need submission.

इस शर्त के पालन में लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) ने पत्र क्रमांक 4147 दिनांक 21.05.2024 से अवगत कराया है कि प्रस्तावित खदान संजय टाईगर रिजर्व / बगदरा / सोन घड़ियाल अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र का टाईगर / हाथी कॉरीडोर एवं ईको सेंसेटिव जोन का भाग नहीं है। सिंगरौली वनमण्डल की वर्तमान में प्रभावशील कार्य आयोजना (अवधि 2019–20 से 2028–29) के अनुसार धिरौली कोल ब्लॉक हाथी कॉरीडोर में सम्मिलित नहीं है। धिरौली कोल ब्लॉक से हाथी कॉरीडोर की दूरी न्यूनतम 5 कि.मी. की है। क्षेत्र संचालक, संजय टाईगर रिजर्व, सीधी ने साथ ही यह भी अवगत कराया है कि संजय टाईगर रिजर्व के ईको सेंसेटिव जोन से इस खदान की दूरी 10.386 कि.मी. की है।

o/c

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) ने यह भी अवगत कराया है कि इस क्षेत्र में फ्लोरा एवं फौना के संरक्षण के लिये रू. 10.65 करोड़ वन्यप्राणी प्रबंधन योजना उनके कार्यालय द्वारा अनुमोदित की गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के पत्र की प्रति परिशिष्ट–1 में संलग्न है।

iii. The proposed forest land is having density of forests ranging from 0.4 to 0.6 density wherein 5,70,666 no. of trees are estimated to be affected from the proposed activities. The detail of the forest crop sand diameter classes of valuable trees estimated needs to be elaborated and phase wise felling details should also be indicated.

इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर खड़े वृक्षों का प्रजातिवार तथा गोलाईवार विवरण प्रस्ताव के भाग–2 में बिन्दु 4(ii) में अंकित है।

इस प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि से वृक्षों के विदोहन के संबंध में आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि यह कार्य खनन कार्य शुरू होने से 40 साल की समयावधि के अन्दर चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा। इस अवधि के दौरान खनन क्षेत्र कों समतल कर वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रकरण में प्रभावित लगभग 5,70,666 पेड़ों की कटाई के एवज में चरणबद्ध रूप से लगभग 36,38,165 पेड़ लगाए जाएंगे। आवेदक संस्था द्वारा इस प्रस्ताव में काटे जाने वाले वृक्षों तथा लगाये जाने वाले पौधों का चरणबद्ध कार्य निम्नानुसार किया जाना प्रतिवेदित किया है :–

		Land Requirement (ha.)		Plantation on Reclaimed Land (Ha.)			Number of Tree Planted		
Phasing of Land	Years from start of mining Operation	Forest Land	Tentative no of tree to be felled	Plantation area in forest Land (ha.)	Plantation area in Non Forest Land (ha.)	Total Plantation area	Plantation in forest land (Nos)	Plantation in non-forest land (Nos)	Total Plantation (Nos)
Phase I	1 to 3	345.33	141011	4	16	20	10000	40000	50000
Phase II	4 to 5	300.17	122570	32	8	40	48000	12000	60000
Phase III	6 to 10	237.06	96800	224	259.57	483.57	336000	389355	725355
Phase IV	11 to 15	136.17	55603	150	76.94	226.94	225000	115410	340410
Phase V	16 to 20	220.41	90001	150	74.77	224.77	225000	112155	337155
Phase VI	21 to 30	108.66	44370	200	123.62	323.62	300000	185430	485430
Phase VII	31 to 40	49.74	20311	200	210.45	410.45	300000	315675	615675
Final Closure		0	0	437.54	245.22	682.76	656310	367830	1024140
Total		**1397.54**	**570666**	**1397.54**	**1014.57**	**2412.11**	**2100310**	**1537855**	**3638165**

आवेदक संस्था ने यह भी अवगत कराया है कि उपरोक्त रोपण इस प्रस्ताव में समतुल्य 1400 हेक्टेयर गैर वनभूमि पर किये जाने वाले क्षतिपूर्ति रोपण के अतिरिक्त होगा।

iv. The method of mining has been reported in the online application as Opencast + Underground. However the State Govt. in their reference letter has mentioned the same as open cast method of mining. The state govt shall therefore examine the same and report whether the proposal is for underground mining, open cast mining or both. The detail of area proposed for OCP and underground mining including the component wise KML file shall be submitted.

आवेदक संस्था ने यह भी अवगत कराया है कि इस खदान में कोयला कुल 09 सतहों (Seams) में उपलब्ध है। इन 09 सतहों (Seams) में से 05 सतहों (Seams) में कोयला खुली खदान के रूप में तथा 04 सतहों (Seams) में कोयला भूमिगत खनन से निकाला जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार इस प्रस्ताव में आवेदित वनक्षेत्र 1397.54 में प्रथमतः खुली खदान के माध्यम से खनन किया जायेगा। तत्पश्चात इसी 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि में भूमिगत खदान के माध्यम से खनन किया जायेगा।

आवेदक संस्था ने यह भी अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत माईनिंग प्लान के अनुसार इस खदान से खुली खदान के रूप में 05 सतहों (Seams) में कोयला निकाला जाना प्रस्तावित है। खुली खदान से कुल 186.06 मिलियन टन कोयला तथा भूमिगत खदान से कुल 112.07 मिलियन टन कोयला निकाला जाना है। इस प्रकार खुली खदान से कोयला कुल मात्रा का लगभग 62.4 प्रतिशत निकाला जाना है। आवेदक संस्था ने इस प्रकार यह अवगत कराया है कि यदि खदान भूमिगत की जाती है तो लगभग 62.4 प्रतिशत कोयला खनन से वंचित रह जायेगा।

प्रत्येक सतह (Seam) से निकलने वाले कोयले का विवरण आवेदक संस्था द्वारा अपने उत्तर के बिन्दु क्रमांक–iv में दिया गया है।

आवेदक संस्था द्वारा यह भी लेख किया गया है कि सिंगरौली जिले में 15 से अधिक खदाने है। ये सभी खदानें ओपन कास्ट खदानें है कुछ खदाने 200 मीटर से भी अधिक गहराई पर काम कर रही है जैसेः– दुधीचुआ ओसीपी विस्तार (कार्य की अधिकतम गहराई 310 मीटर), निगाही विस्तार ओसीपी (कार्य करने की अधिकतम गहराई 300 मीटर), बन्धा कोयला ब्लॉक (प्रस्तावित अधिकतम गहराई 230 मीटर), सुलियारी कोयला खदान (कार्य करने की अधिकतम गहराई 240 मीटर।

आवेदक संस्था के इस कथन से यह कार्यालय सहमत है। सिंगरौली जिले में एन.सी.एल., रिलायंस, जय प्रकाश एसोसिएट, टी.एच.डी.सी. आदि संस्थाओं की अनेको खदानें हैं। यह सभी खदानें खुली खदाने हैं तथा इन सभी खदानों में किसी में भी भूमिगत खनन के माध्यम से कोयला उत्पादित नहीं होता है।

v. As per DSS analysis the proposed area is falling in Inviolate or In High conservation zone value (HCV) with majority area falling in Very Dense Forest category. The state shall submit the justification for proposing such pristine area for mining. Further, keeping in view the conservation value of the area, the state shall intimate whether any impact assessment/biodiversity study taking into account the impact of mining has been carried out or not. If so the details be provided.

इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि इस खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये उनके द्वारा EIA अध्ययन करवाया गया है। इस अध्ययन में biodiversity study का मूल्यांकन/अध्ययन भी किया गया है। आवेदक संस्था द्वारा इस संबंध में किये गये अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्ताव के भाग–1 में अतिरिक्त जानकारी के बिन्दु क्रमांक–42 पर अपलोड कर दी गई है, जिसका अवलोकन पोर्टल पर किया जा सकता है।

सिंगरौली जिले में कोयला वनक्षेत्रों में बहुतायत में हैं। पूर्व में भी इसी घनत्व के वनक्षेत्रों में एन.सी.एल. को बीना कांकरी / निगाही/दूधीचूआ की खदाने स्वीकृत की गई है।

vi. Satellite imagery and Land use plan submitted by the user agency reveals that there are five (5) transmission lines which are passing through the proposed forest land for diversion. The copy of approvals granted under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan), Adhiniyam, 1980 along with NoC from concerned agencies to shift the power lines from the proposed area have not been submitted. The state shall therefore submit the copy of approvals under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan), Adhiniyam, 1980 and the copies of NOC form the concerned agencies. The state shall also intimate whether any additional forest land would be required for the shifting of transmission lines or not along with details.

इस शर्त पालन में आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि इन 05 ट्रांसमिशन लाईन में से 04 ट्रांसमिशन लाईन पावरग्रिड कार्पोरेशन की तथा 01 ट्रांसमिशन लाईन मध्यप्रदेश ट्रांसमिशन कम्पनी की है।

आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि मध्यप्रदेश ट्रांसमिशन कम्पनी की 01 ट्रांसमिशन लाईन को डायवर्ट करने की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। यह स्वीकृति भारत सरकार से प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/TRANS/155291/2022; 21.372 Ha में प्राप्त हो चुकी है।

आवेदक संस्था ने यह भी अवगत कराया है कि पावरग्रिड कार्पोरेशन की 04 ट्रांसमिशन लाईनों को डायवर्ट करने की कार्यवाही प्रचलित है।

vii. Presence of water bodies like Nala/ Tributary are also visible in the proposed forest land. The state shall submit the detail of mitigation measures in this regard along with the NoC/permission from the concerned department.

इस शर्त के पालन में आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि प्रभावित वनक्षेत्र से बहने वाले नाले की "Hydrology Report" for management of Nala tributaries in & around Dhirauli Coal Block तैयार कर ली गई है तथा इसकी DPR की स्वीकृति जल संसाधन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 2512/G/W/MP/1-48 dated 19.04.2022 से प्राप्त की गई है। आवेदक संस्था द्वारा इस संबंध में जल संसाधन विभाग से प्राप्त स्वीकृति की प्रति प्रस्ताव के भाग–1 में अतिरिक्त जानकारी के बिन्दु क्रमांक–31 पर अपलोड कर दी गई है, जिसका अवलोकन पोर्टल पर किया जा सकता है।

viii. The proposal involves diversion of 1397.54 ha forest land out of which 225.4 ha has been proposed for external dumping and 6.3 ha has been earmarked for infrastructure which are non-site specific. The details of total overburden area in the proposal involving both forest as well as non forest land has not been submitted, which is required to be done. The state shall also explore the possibility of shifting of theses components on non-forest land.

इस शर्त के संबंध में आवेदक संस्था ने अवगत कराया है कि इस खदान से खुले खनन से लगभग 186.06 मिलियन टन कोयला उत्पादित होगा। इस खुले खनन से लगभग 1963.55 मिलियन टन ओवरवर्डन उत्पादित होगा। इस ओवरवर्डन को डम्प करने के संबंध में आवेदक संस्था ने अपने उत्तर में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है जो बिन्दु क्रमांक–viii में अंकित है।

ix. As per the component wise breakup an area of 67.11 ha is designated as undisturbed area. The purpose and reason for including the same in the instant proposal has not been submitted.

इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा अपने उत्तर में विवरण दिया है जो बिन्दु क्रमांक–ix में अंकित है।

x. Compensatory Afforestation has been proposed in total 45 patches comprising an area of 1397.523 ha wherein two CA patches namely Village Imlipura, Khasra No 2 and 19, Shivpuri District are falling in the Forest compartment boundary as per DSS analysis. Moreover, these two patches are also located in Tiger corridor. The state shall examine the matter and ensure to provide NFL for CA as per guidelines. The CA sites namely Village Dhandheda Kanad (Kh No 102,80,139,103), Village Raipuriya (Kh No 78, 128 and 105) are located on the earthen dam, which may not be suitable for raising CA and the land may not be free from all encumbrances. Further, the documentary evidence of proposed CA .site namely Village: Raghunathapura (Survey No. 3), Shivpuri District revealed that the ownership of land is with the Forest Department. The state shall examine the issues as above and ensure that all the CA areas are suitable, free from encumbrances and eligible for the purpose of CA as per prescribed guidelines.

इस बिन्दु के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक 2097 दिनांक 24.05.2024 से अवगत कराया गया है कि ग्राम ईमलीपुरा के खसरे क्रमांक 2 एवं 19 के मानचित्र को वनखण्ड के मानचित्र पर ओवरलेप करने पर यह पाया गया कि यह खसरे वनक्षेत्र से बाहर पाये गये हैं। वनमण्डलाधिकारी, शिवपुरी द्वारा अवगत कराया गया है कि यह भूमि गैर वनभूमि है तथा वनक्षेत्र के पूर्णतः बाहर है। इसी प्रकार वनमण्डलाधिकारी, शिवपुरी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि ग्राम रघुनाथपुरा के खसरे क्रमांक 3 की भूमि वनक्षेत्र के बाहर होकर वनक्षेत्र की सीमा से लगी होना पाया गया है। यह भूमि वन विभाग के अधिपत्य में नहीं है तथा शासकीय राजस्व भूमि है। वनमण्डलाधिकारी, शिवपुरी के पत्र की प्रति परिशिष्ट–2 में संलग्न है।

जिला आगर–मालवा के ग्राम धनखेड़ा में उपलब्ध कराई गई 30 हेक्टेयर गैर वन भूमि के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, शाजापुर द्वारा अवगत कराया गया है कि खसरा क्रमांक 103 में ग्राम पंचायत द्वारा मिट्टी का बांध बनाया गया है। इस बांध के पानी का उपयोग वृक्षारोपण क्षेत्र के पौधों में किया जा सकता है। इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा गूगल पर तालाब के रकबे की गणना की गई। गणना में तालाब का रकबा लगभग 2 हेक्टेयर है। अतः शेष 28 हेक्टेयर में 3 मीटर x 3 मीटर के अंतराल पर 30000 पौधें आसानी से लगाये जा सकते हैं। तालाब होने के कारण पौधों की सिंचाई करना भी सम्भव हो सकेगा।

इस प्रकार जिला आगर–मालवा के ग्राम रायपुरिया में आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई 5.22 हेक्टेयर गैर वनभूमि के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, शाजापुर द्वारा अवगत कराया गया है कि खसरा क्रमांक 78 में ग्राम पंचायत द्वारा मिट्टी का बांध बनाया गया है। इस बांध के पानी का उपयोग वृक्षारोपण क्षेत्र के पौधों में किया जा सकता है। इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा गूगल पर तालाब के रकबे की गणना की गई। गणना में तालाब का रकबा लगभग 0.1 हेक्टेयर है। अतः शेष 5.12 हेक्टेयर में 3 मीटर x 3 मीटर के अंतराल पर 5220 पौधें आसानी से लगाये जा सकते हैं। तालाब होने के कारण पौधों की सिंचाई करना भी सम्भव हो सकेगा।

वनमण्डलाधिकारी, शाजापुर के पत्र की प्रति परिशिष्ट–3 में संलग्न है।

xi. Mode of mineral/ coal transportation route and how the requirement of electricity and water will be met has not been given in the proposal. The state shall therefore submit the detailed mineral evacuation plan along with the details as to how the requirement of electricity and water would be met. The detail of additional forest land required for the purpose(if any) shall also be submitted.

इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा अपने उत्तर में विवरण दिया है जो बिन्दु क्रमांक–xi में अंकित है।

xii. In accordance with the Para 7.8(i) of Chapter 7 of the consolidated guidelines and clarification issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Rules, 2023, the State govt shall give the justification for the necessity of opening the new mining lease along with details.

इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि बिजली की बढती मांग को देखते हुये कोयले का उत्पादन बढाया जाना आवश्यक है। कोयले की बढ़ती मांग को देखते हुये कोयला मंत्रालय द्वारा समय–समय पर कोल ब्लॉक को नीलाम किया गया है।

xiii. The Quantitative values on the parameters such as Cost of Human resettlement, Loss of public facilities has not be ascertained in the Cost-Benefit analysis, which is required to be done.

इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा अपने उत्तर में विवरण दिया है जो बिन्दु क्रमांक–xiii में अंकित है।

xiv. As per the SIR of the DFO, Singrauli Division, rights of 49 leaseholder have been recognized in the proposed area. The state shall submit details of the same and status of R&R plan.

इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा अपने उत्तर में विवरण दिया है जो बिन्दु क्रमांक–xiv में अंकित है।

xv. As per the 3-D subsidence prediction study report Maximum tensile strain reported in the proposed area is 17.47. The state shall examine the same and submit its comments in case the proposal is for underground mining only.

इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा अपने उत्तर में विवरण दिया है जो बिन्दु क्रमांक–xv में अंकित है।

आपके द्वारा उपरोक्त 15 बिन्दुओं के अतिरिक्त पत्र दिनांक 15.05.2024 से इस खदान को भूमिगत खदान के रूप में करने के संबंध में राज्य शासन का अभिमत चाहा गया है। यह विषय तकनीकी होने के कारण इस बिन्दु पर राज्य शासन के माध्यम से खनिज विभाग का अभिमत चाहा गया। खनिज विभाग द्वारा अभिमत दिया गया है कि यह खदान भूमिगत खदान के रूप में संचालित करना सम्भव नहीं है। खनिज विभाग के द्वारा दिया गया अभिमत परिशिष्ट–4 पर संलग्न है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारियां पूर्ण हो गई है। इस प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

30.05.24

(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–1 / 845 / 2022 / 10–11 / 2856 भोपाल, दिनांक 30/05/2024

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश ।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
3. मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रायवेट लिमिटेड, मुम्बई की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

30.05.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट – 1

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

भू–तल, सी–ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड़ नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003
दूरभाष : 0755–2674248, 2524275, फैक्स : 0755–2674206 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / व.प्रा. / तक.–1. / MINE.-103/ 4147 भोपाल, दिनांक : 21/05/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :– **वनमण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न, माडा पूर्व सरई के विभिन्न आर.एफ. वन कक्षों के रकबा 1335.35 हेक्टेयर वनभूमि तथा विभिन्न खसरों को रकबा 6.19 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल भूमि 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक अंतर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा ऊपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन–मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा.लि. का ऑन लाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MINE/142344/2021**

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / एफ–1 / 845 / 2022 / 10–11 / 846 दिनांक 06.02.2023 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / व.प्रा. / तक.–1. / MINE.-103/2532 दिनांक 26.03.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र से आपके द्वारा विषयांकित प्रकरण के संबंध में भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8–01 / 2024–एफसी दिनांक 02.02.2024 में उल्लेखित 15 बिन्दुओं में से निम्नानुसार बिन्दु क्रमांक– ii के संबंध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, म.प्र. का अभिमत चाहा गया है।

ii The Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary is located a distance of 10.07 KM from the proposed Forest land for diversion. Morever the State Govt, informed that the proposed area is falling within the 1 KM of the elephant corridor as per the prevailing working plan for the period 2019-20 to 2028-29. Further, movement of leopard (Tendua) reported in the SIR of the DFO, Singrauli Therefore, the comments from CWLW along with proposed mitigation measures need submission.

उक्त संबंध में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 26.03.2024 से वांछित अभिमत प्रेषित किया गया था। उक्त संबंध में क्षेत्र संचालक, संजय टाइगर रिजर्व, सीधी द्वारा पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 3092 दिनांक 14.05.2024 से संशोधित प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। उक्त प्रतिवेदन अनुसार निम्नानुसार अभिमत प्रेषित किया गया है:–

1. प्रस्तावित माइन क्षेत्र संजय टाइगर रिजर्व / बगदरा एवं सोन घड़ियाल अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र / टाइगर / हॉथी कॉरीडोर एवं ईको सेंसेटिव जोन का भाग नहीं है। वर्तमान में प्रभावशील कार्य आयोजना अवधि 2019–20 से 2028–29 के आलेख भाग–2 के पृष्ठ क्रमांक 442 के अनुसार तथा वनमण्डल अधिकारी, सिंगरौली के पृष्ठांकन पत्र क्रमांक / तक / 2895 दिनांक 06.05.2024 के अनुसार धिरौली कोल ब्लाक हाथी कॉरीडोर में सम्मिलित नहीं है, तथा धिरौली कोल ब्लाक से हाथी कॉरीडोर की न्यूनतम दूरी 05 कि.मी. है। कार्य आयोजना संलग्न डिजिटल मानिचत्र की प्रति संलग्न है।
2. प्रस्तावित माइन क्षेत्र से संरक्षित क्षेत्र संजय टाइगर रिजर्व के ईको सेंसटिव जोन की सीमा से 10.386 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
3. प्रस्तावित माइन क्षेत्र की आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई के.एम.एल. फाईल संलग्न है। जिसमें पृथक से अक्षांश–देशांश की आवश्यकता नहीं है।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक / व.प्रा. / मा.चि. / 2022 / MINE-140 / 8522 दिनांक 24.11.2022 के पेज 02 के अनुसार वन्यप्राणी प्रबंध योजना के पृष्ठ क्रमांक 21 से 49 में उल्लेखित फ्लोरा–फॉना के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के पृष्ठ क्रमांक 98 से

101 पर दर्शाए गयों कार्यो के अनुसार राशि रूपये 1065.00 लाख की 10 वर्षो की योजना का अनुमोदन किया गया है। पत्र में यह भी उल्लेखित है कि प्रकरण में भारत सरकार/ राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति के उपरान्त माइन प्रारम्भ होने के पूर्व समय–सीमा में संशोधित वन्यप्राणी संरक्षण योजना में वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु प्रावधानित राशि रूपए 1065.00 लाख मध्यप्रदेश टाइगर फाउन्डेशन सोसायटी, भोपाल के स्थान पर कैम्पा मद में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिजर्व सीधी द्वारा प्रेषित उक्त प्रतिवेदन/अभिमत से सहमति व्यक्त करते हुये तदानुसार इस कार्यालय का **संशोधित अभिमत** आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

21/5/2024

(डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

पृ0 क्रमांक/व.प्रा./तक.–1./MINE.-103/ 4148 भोपाल, दिनांक : 21/05/2024

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्र संचालक, संजय टाइगर रिजर्व, सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मेसर्स स्ट्राटटेक मिनरल्स रिसोर्सेज प्रा. लि. अडानी कार्पोरेट हाऊस, शांतिग्राम एस.जी. हाइवे, अहमदाबाद, गुजरात की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

21/5/2024

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

परिशिष्ट – 2

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी (म0प्र0)

दूरभाष एवं फैक्स नं 07492-221012 ई मेल dfotshivp@mp.gov.in मोबाइल : 9424794737

क्रमांक/डी.एम./2024/ 2097 शिवपुरी, दिनांक/ 24/05/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू प्रबन्ध)
वन भवन भोपाल (म.प्र.)

विषयः– वनमण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न , माड़ा पूर्व सरई के विभिन्न आर एफ वन कक्षों के रकवा 1335.35 हेक्टेयर वन भूमि तथा विभिन्न खसरों की रकवा 62.19 हैक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल 1397.54 हेक्टेयर वन भूमि में धिरौली कोल ब्लॉक अंतर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा उपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का – मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा0लि0 का ऑन लाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/142344/2021

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 8–01/2024–एफ सी दिनांक 02.02.2024 एवं आपका पृष्ठांकन क्रमांक एफ –1/845/2022/10–11/ 847 भोपाल दिनांक 06.02.2024

––00––

विषयांकित के संबंध मे एवं संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा0लि0 का ऑन लाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/142344/2021 में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा चाही गई जानकारी में बिन्दु क्रमांक X से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :–

तहसील बैराड़ ग्राम इमलीपुरा के शासकीय सर्वे नम्बर 02 प्रस्तावित रकवा 18.18 हैक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 19 प्रस्तावित रकवा 23.72 हेक्टेयर पी एफ ब्लॉक इमलीपुरा की अधिसूचना संलग्न ब्लॉक मैप अनुसार के एम एल. फाइल एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र की के.एम. एल. फाइल को ओवरलेप कर मिलान किया ,जिससे यह स्थिति स्पष्ट होती है कि ये नॉन फोरेस्ट लैण्ड है वन क्षेत्र से पूर्णतः बाहर है एवं शासकीय राजस्व भूमि है ।

तहसील बैराड़ ग्राम रघुनाथपुरा के शासकीय सर्वे नम्बर 03 प्रस्तावित रकवा 6.00 हैक्टेयर पी एफ ब्लॉक बेहरदा के कार्य आयोजना के मानचित्र अनुसार के.एम एल. फाइल एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र की के.एम.एल. फाइल को ओवरलेप कर मिलान किया ,जिससे यह स्थिति स्पष्ट होती है कि ये नॉन फोरेस्ट लैण्ड वन क्षेत्र की सीमा से लगा हुआ है एवं वन विभाग के अधिपत्य में नही है तथा यह शासकीय राजस्व भूमि है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

24/05/24
(सुधांशु यादव)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (म.प्र)

पृ०क्रमांक/डी.एम./2024/ 2098 शिवपुरी, दिनांक/ 24/05/2024

प्रतिलिपि :–

1. वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ ।
3. मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा0लि0 अडानी कॉर्पोरेट हाउस शांति ग्राम एस जी.हाईवे अहमदाबाद गुजरात की ओर सूचनार्थ ।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (म.प्र)

परिशिष्ट-3

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शाजापुर (म.प्र.)

पता : टेलीफोन टॉवर के पास ए.बी. रोड़ शाजापुर (म.प्र.) पिन 465001
ई–मेल : dfotsjpur@mp.gov.in,

क्रमांक / माचि / 2024 / 2257 शाजापुर, दिनांक 21/5/24

प्रति,

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

विषय : वनमंडल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न, माड़ा पूर्व सरई के विभिन्न आर.एफ वन कक्षों के रकबा 1335.35 हे. वन भूमि तथा विभिन्न खसरों की रकबा 62.19 हे. राजस्व वनभूमि कुल 1397.54 हे. वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक अंतर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खन्न तथा उपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का– मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्राइवेट लिमिटेड का ऑनलाईन प्रस्ताव क. FP/MP/MIN/142344/2021

संदर्भ : प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र कमांक / एफ–1 / 845 / 2022 / 10–11 / 846 –847 दिनांक 06.02.2024

------0------

विष्यान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में प्रकरण में भारत सरकार द्वारा बिंदु क. 10 वनमण्डल शाजापुर से संबंधित भाग "Compensatory afforestation has been proposed in total 45 patches comprising an area of 1397.523 hectare wherein two patches namely village Imlipura, khasra no 2 and 19, Shivpuri District are falling in the Forest compartment boundary as per DSS analysis, moreover, these two patches are also located in Tiger corridor. The state shall examine the matter and ensure to provide NFL for CA as per guidelines. **The CA sites namely Village Dhandeda kanad (khasra no 102,80,139,103), Village Raipuriya (khasra no 78, 128 and 105) are located on the earthen dam, which may not be suitable for raising CA and the land may not be free from all encumbrances**. Further, the documentary evidence of proposed CA site namely Village Raghunathpura (survery no 3), Shivpuri Disrtrict revealed that the owership of land is with the forest Department. The state shall examine the issues as above and ensure that all the CA areas are suitable, free from encumbrances and eligible for the purpose of CA as per prescribed guidelines." के सबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी आगर द्वारा उनके पत्र क. 456 दिनांक 16.03.2023 से मौका स्थल की जांचकर निम्नानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया हैः–

1. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम धंदेडा कानड़ में सर्वे क. 102, 80, 139 में कोई भी मिट्टी के बांध / तालाब नही बनाया गया है एवं सर्वे क. 103 में लगभग 4.00 हेक्टेयर पर ग्राम पंचायत के द्वारा मिट्टी के बांध बनाकर तालाब निर्माण का कार्य किया गया है, जिसका उपयोग वृक्षारोपण की सिंचाई में उपयोग किया जा सकता है। उपरोक्त प्रस्तावित स्थल वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।
2. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम रायपुरिया सर्वे क. 128 में कोई भी मिट्टी के बांध / तालाब नही बनाया गया है, सर्वे क. 78 में लगभग 2.00 हेक्टेयर में ग्राम पंचायत के द्वारा मिट्टी के बांध बनाकर तालाब निर्माण का कार्य किया गया है, जिसका उपयोग वृक्षारोपण की सिंचाई में उपयोग किया जा सकता है एवं सर्वे क. 105 में लगभग 0.04 हेक्टेयर में ग्रमीणों द्वारा गड्डा खोदा गया है, जिसका वर्तमान में कोई उपयोग नही किया जाता है। उपरोक्त प्रस्तावित स्थल वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

उपयोगकर्ता संस्था मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्राइक्टे लिमिटेड द्वारा ग्राम धंदेडा कानड़ में सर्वे क. 103 में लगभग 4.00 हेक्टेयर पर एवं ग्राम रायपुरिया सर्वे क. 78 में लगभग 2.00 हेक्टेयर में निर्मित तालाबो का उपयोग ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों द्वारा नही किये जाने के संबंध मे वचन पत्र दिया है कि उक्त ग्रामों की भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटन कें पूर्व ग्राम पंचायतों से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जावेगा (वचन पत्र संलग्न है)।

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन अनुशंसा सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित है। कृपया उक्त प्रतिवेदन संदर्भित पत्र में दिये निर्देशानुसार वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

Scanned with CamScan

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 2258 शाजापुर, दिनांक– 21/5/24

प्रतिलिपि–

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

Scanned with CamScan

परिशिष्ट-4

...बीस-र सचिवालय

का विभाग

विषय वन मंडल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न, माडा, पूर्व सरई के विभिन्न आर.एफ. वनकक्ष के रकबा 1335.35 हेक्टेयर वनभूमि तथा विभिन्न खसरों के रकबा 62.19 हेक्टेयर राजस्व भूमि कुल रकबा 1397.54 हेक्टेयर वन भूमि मे धिरौली कोल ब्लॉक अंतर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा ऊपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का- मेसर्स स्ट्राट्टेक मिनरल्स रिर्सोर्सेस प्रा.लि. का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक **FP/MP/MIN/142344/2023.**

अपर मुख्य सचिव, वन विभाग की कार्यालयीन नस्ती क्रमांक आर 2052309/2024/10-3 के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में खनिज साधन विभाग से अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु लेख किया गया है। प्रकरण में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. में पदस्थ भू-वैज्ञानिक से तकनीकी प्रतिवेदन प्राप्त कर पृथक से अनुलग्नों सहित संलग्न है।

प्राप्त तकनीकी प्रतिवेदन में निम्नानुसार निष्कर्ष दिये गये हैं :-

1) वन विभाग द्वारा जिन वन कक्षों में (आर.एफ. 360, 364, 370 तथा 371) भूमिगत खनन हेतु अनुशंसा की गई है, वहाँ कोल सीम उथली गहराई (35 से 163 मीटर) में अवस्थित है।
2) इन वनकक्षों में कोल सीम की सामान्य मोटाई 10-12 मीटर है।
3) इन वनकक्षों में वर्टीकल स्ट्रिपिंग अनुपात 8 घनमीटर प्रतिटन से कम है।
4) इन वनकक्षों में कोल सीम के ऊपर का आवेरलेइंग स्ट्रेटा की कंप्रेसिव स्ट्रैंथ (6 से 17 **MPa**) है, जो कि भूमिगत खनन हेतु कम होने से खदान में भूमि धसाव/खदान धसने का कारण हो सकती है तथा कम गहराई (35 से 163 मीटर) होने के कारण भूमिगत खनन हेतु उपयुक्त नही है।

उपरोक्तानुसार प्रश्नाधीन वन क्षेत्रों में अवस्थित रॉक स्टेटा की भौतिक यांत्रिक गुण (Physico-mechanical properties) मोटाई, कोल सीम की सतह से गहराई ओवर बर्डन की मोटाई, वर्टीकल स्ट्रिपिंग अनुपात खनिज संरक्षण के दृष्टिगत आदि बिन्दुओं के आधार पर प्रश्नाधीन वन कक्ष क्रमांक 360, 364, 370 तथा 371 की कोल सीम क्रमांक VI, VII, VIII मे भारत सरकार कोयला मंत्रालय से अनुमोदित खनन योजना अनुसार ओपन कॉस्ट तकनीक से खनन किया जाना संभव है।

शाo.मु —768— इनि. मुभो—27-12-23—5,00,000.

F MIN/1/0001/2024/MRD-12
Com. No.- 317801
(4) R-2062721

विषय : वन मंडल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न, माडा, पूर्व सरई के विभिन्न आर.एफ. वनकक्ष के रकबा 1335.35 हेक्टेयर वनभूमि तथा विभिन्न खसरों के रकबा 62.19 हेक्टेयर राजस्व भूमि कुल रकबा 1397.54 हेक्टेयर वन भूमि मे धिरौली कोल ब्लॉक अंतर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा ऊपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का- मेसर्स स्ट्राट्टेक मिनरल्स रिर्सोर्सेस प्रा.लि. का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक **FP/MP/MIN/142344/2023.**

उपरोक्तानुसार तकनीकी टीप (मय 8 सह-लग्नकों सहित पृथक से) अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

अपर सचिव
म.प्र.शासन खनिज साधन विभाग

प्रमुख सचिव
खनिज साधन विभाग

पृ०-1/न पर चाहे गये अभिमत के अनुक्रम में पृ० 3-4/न पर विभाग की टीप प्रस्तुत है

29/5
(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

ACS
Forest

ACS Sir के निर्देशानुसार नस्ती आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है

30/5
(अतुल कुमार मिश्रा)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

APCCF (LM)

Mining

30/05/24

छत्तीस-2 सचिवालय
का विभाग

नस्ती क्र. 1353/.../वा/20
आवक दि. 29.5.24
जावक 30/5/24

393/PSMRD/24
29/05/2024

Technical Report on observation given by the MOEF on underground mining in village Dhirauli Coal block of Singruli District in Forest compartments no RF 360, 364 , 370 & 371

As per the Instruction given by the Department on above matter the point wise technical report with the factual fact are as follows.

- The Coal Block has been owned by M/s Stratatech Mineral Resource Private Limited (SMRPL) under commercial coal block auction and vest by Nominated Authority MoC, GoI vide Letter No. NA-104/7/2020-NA dated 03.03.2021.Mining plan and mine closure plan of the block is approved by MoC on 04.05.2021 (MPS-34011-26-2019-MPS) **annexure 1 & 2.**
- As per the approved mining plan by the MoC initially opencast mining of coal is proposed.
- As per observation / instructions given by the MoEF letter dated 02/02/2024 and 15/05/2024 **(annexure 3)** in forest compartment numbers RF 360 , 364, 370 & 371 the underground mining is advisable on this point the technical fact are as follows:-

1. As per the Geological Report prepared by MECL, physico-mechanical test done by CMPDI the strength of overlying strata is ranging from 6 to 17 MPa (excludes top 15 meter top soil) which is not at all suitable for underground working. Initial 110 meter analysis report is given below for ready reference and detail report is attached as **annexure 4** taken from Geological Report prepared by MECL physico-mechanical properties analyzed CMPDI Ranchi the core samples of borehole MSD 21 UCS (Uni-axial compressive strength) value is not feasible the for the

underground mining as per the compressive strength of the value rock is showing the weaker strata , this may causes the subsidence or collapse of mines, It means the underground mining are not safe in the RF 360 , 364, 370 & 371 for seam VI,VII & VIII. Same study has been done by the Visvesaraiya National Institute of Technology Nagpur in borehole no MDP-15 which also revealed the same results.

2. The Limit of Stripping ratio given in approved mining plan is 10.55 Cum/T while the overall stripping ratio of forest compartment no RF 360 , 364, 370 & 371 is less than 8 Cum/T henceforth the stripping ratio is under the limit for the opencast mining.

3. As per approved mining plan Opencast mining is proposed in Seam VI,VII & VIII (including splits) and underground mining are proposed in seam, IV, III-Top and II. It means the underground mining is proposed below the opencast mining.

4. As per approved mining plan, extractable reserve by opencast mining is 186.06 Mt and estimate OB volume is 1963.55 MBCM with stripping ratio of 10.55 cum/t.Box cut is planned from southern side of block boundary and 259.01 MBCM OB is to be placed as external dump.

Year	External Dump		Internal Dump		Total OB	
	Progressive (Mcum)	Cumulative (Mcum)	Progressive (Mcum)	Cumulative (Mcum)	Progressive (Mcum)	Cumulative (Mcum)
Yr-1	16.35	16.35	-	-	16.35	16.35
Yr-2	28.12	44.47	-	-	28.12	44.47
Yr-3	19.36	63.83	13.94	13.94	33.3	77.77
Yr-4	12.39	76.22	20.76	34.7	33.15	110.92
Yr-5	11.64	87.86	21.53	56.23	33.17	144.09
Yr-6	10.5	98.36	24.3	80.53	34.8	178.89
Yr-7	11.34	109.7	24.66	105.19	36	214.89
Yr-8	11.55	121.25	25.7	130.89	37.25	252.14
Yr-9	11.97	133.22	26.33	157.22	38.3	290.44
Yr-10	12.11	145.33	26.49	183.71	38.6	329.04
Yr-11	12.81	158.14	27.49	211.2	40.3	369.34
Yr-12	13.02	171.16	28.73	239.93	41.75	411.09
Yr-13	13.58	184.74	30.32	270.25	43.9	454.99
Yr-14	13.79	198.53	32.11	302.36	45.9	500.89
Yr-15	14.42	212.95	32.88	335.24	47.3	548.19
Yr-16	14.91	227.86	34.09	369.33	49	597.19
Yr-17	15.33	243.19	34.72	404.05	50.05	647.24
Yr-18	15.82	259.01	35.03	439.08	50.85	698.09
Yr-19	-	259.01	51.4	490.48	51.4	749.49
Yr-20	-	259.01	52.25	542.73	52.25	801.74
Yr-21	-	259.01	53.3	596.03	53.3	855.04
Yr-22	-	259.01	54.25	650.28	54.25	909.29
Yr-23	-	259.01	55.75	706.03	55.75	965.04
Yr-24	-	259.01	58.25	764.28	58.25	1023.29
Yr-25	-	259.01	60.75	825.03	60.75	1084.04
Yr-26	-	259.01	62.75	887.78	62.75	1146.79
Yr-27	-	259.01	64	951.78	64	1210.79
Yr-28	-	259.01	64.5	1016.28	64.5	1275.29
Yr-29	-	259.01	65.5	1081.78	65.5	1340.79
Yr-30	-	259.01	65.75	1147.53	65.75	1406.54
Yr-31	-	259.01	66.5	1214.03	66.5	1473.04
Yr-32	-	259.01	67.25	1281.28	67.25	1540.29
Yr-33	-	259.01	67.25	1348.53	67.25	1607.54

Year	External Dump		Internal Dump		Total OB	
	Progressive (Mcum)	Cumulative (Mcum)	Progressive (Mcum)	Cumulative (Mcum)	Progressive (Mcum)	Cumulative (Mcum)
Yr-34	-	259.01	67.75	1416.28	67.75	1675.29
Yr-35	-	259.01	68.5	1484.78	68.5	1743.79
Yr-36	-	259.01	68.5	1553.28	68.5	1812.29
Yr-37	-	259.01	69.25	1622.53	69.25	1881.54
Yr-38	-	259.01	53.5	1676.03	53.5	1935.04
Yr-39	-	259.01	21.5	1697.53	21.5	1956.54
Yr-40	-	259.01	7.01	1704.54	7.01	1963.55
Total	**259.01**	**259.01**	**1704.54**	**1704.54**	**1963.55**	**1963.55**
	259.01		**1704.54**		**1963.55**	

5. Surface plan and conceptual plan from approved mining plan is attached as Annexure 7 & 8 respectively

6. As per the GR borehole location plan and graphical litho-logs of boreholes (Eight) drilled in forest compartments (RF 360 , 364 , 370 & 371) is attached **as annexure 5 & 6** respectively.

7. Based on eight boreholes drilled in these compartments seam occurrences, thickness and depth of seams are tabulated below

Boreholes	Depth Min. (M)	Depth Max. (M)	Coal thickness(m)	OB thickness(m)
RF360				
MD09	35.49	74.53	12.13	62.4
MD13	52.02	59.7	6.68	53.02
RF371				
MD19	106.91	148.33	9.57	138.76

MD22	167.54	208.06	10.57	197.49
RF370				
MDM11	122.52	163.3	12.2	151.1
RF364				
MDM08	83.83	125.81	12.33	113.48
MDM09	85	126.2	11.53	114.67
MDM10	80.46	119.21	11.56	107.65

8. From the above table minimum depth of mining is approx. 35 m and maximum depth of mining is approx. 163 m (upper seams) which is very shallow depth of mining for underground operations. The shallowest depth of coal occurrence is coming in compartment RF 360 which is planned as box-cut in approved mining plan. Based on thickness of coal seam and depth of occurrence of seams , stripping ratio of these compartment is likely to be below 8 cum/t which is favorable only for opencast mine operation.

➢ **Conclusion**

1. Coal Seams occur in these compartments at shallow depth (35m to 163m).
2. General thickness of coal seams in these compartments are approx. 10-12 m.
3. Overall Vertical stripping ratio within these compartments is approx. <8Cum/T.
4. Overlaying strata are not suitable because of low compressive strength (6 to 17 MPa) for underground operation which may cause subsidence/Collapse of mines and are not safe for underground mining as the depth is ranging between 35 to 163m.

The physico -mechanical properties of rock strata , thickness and depth of coal seam, thickness of overburden , stripping ratio , conservation of minerals; of the area in question is taken into consideration. All these criteria is favorable for the opencast mining only for coal seam number VI, VII and VIII in the RF compartment No. 360, 364, 370 and 371. It is also cost effective and good for the conservation of the minerals.

Based on above observations it may concluded that for the four forest compartments (RF 360,364,370 & 371) which are part of opencast mining (for Seam VI,VII & VIII) as per approved mining plan(MPS-34011-26-2019-MPS dated 04.05.2021); are technically may not be suitable for underground mining.

Henceforth, on the basis of above facts/observations, opencast mining is recommended in four forest compartments (RF 360,364,370 & 371) for coal seam numbers VI,VII & VIII.

- **List of Annexure -**

Annexure 1 – Allocation order from Nominated Authority, MoC ,GoI.

Annexure 2 – Approval of Mining Plan by MoC GoI.

Annexure 3 – MoEF letter dated 02/02/204 and 15/05/2024

Annexure 4- Physico-mechanical test report done by CMPDI, Ranchi and Visvesraiya Institute of Technology Nagpur.

Annexure 5- Location plan of Boreholes .

Annexure 6- Graphical Litholog of eight boreholes drilled in forest compartments (RF 360 , 364 , 370 & 371).

Annexure 7- Approved Mining Plan Plate VII for Surface Plan.

Annexure 8- Approved Mining Plan Plate VIII for Conceptual Plan.

(Dr. M. S. Khatediya)
Asstt. Geologist
D.G.M, Bhopal

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में
ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

सूचना का अधिकार

क्र0/तक0/ 3016 सिंगरौली, दिनांक.. 11-05-2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल

विषयः– वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न, माड़ा एवं पूर्व सरई के विभिन्न आर.एफ. वन कक्षों के रकवा 1335.35 हे0 वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकवा 62.19 हे0 राजस्व वनभूमि कुल 1397.54 हे0 वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक अन्तर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा उपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा.लि. का ऑनलाईन प्रस्ताव क. FP/MP/MIN/142344/2021

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र कमांक 6–01/2024–एफसी दिनांक 02.02.2024

2. आपका पृष्ठां कमांक/एफ–1/845/2022/10–11/847 भोपाल दिनांक 06.02.2024

3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड का प्राप्त पत्र दिनांक 11.05.2024

–000–

विषयांतर्गत के संबंध में वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत रकवा 1335.35 हे0 एवं राजस्व वन भूमि रकवा 62.19 हे0 कुल रकवा 1397.54 हे0 भूमि मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड को सिंगरौली जिला में आवंटित धिरौली कोल ब्लाक हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन प्रस्तावित है।

संदर्भित पत्र (2) से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक 6–01/2024–एफसी दिनांक 02.02.2024 में अधिरोपित बिन्दु कमांक i, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, एवं xiv की जानकारी आवेदक संस्थान से टेबुलर फार्म में तैयार करने हेतु लेख किया गया है।

सन्दर्भित पत्र (3) से उक्त बिन्दुओं की जानकारी आवेदक संस्थान से टेबुलर फार्म में प्राप्त कर मूलतः संलग्न कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ0 क्रमांक/तक0/ 3017 सिंगरौली, दिनांक. 11-05-2024

प्रतिलिपि – 1. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली
11/5/2024

Mining.
14/05

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
आवक क्र. 1083
दिनांक 15/5/24
भोपाल

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

भाजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

सूचना का अधिकार

क्र0/तक0/2834 सिंगरौली, दिनांक 02.05.24

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल

विषयः– वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न, माड़ा एवं पूर्व सरई के विभिन्न आर.एफ. वन कक्षों के रकवा 1335.35 हे0 वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकवा 62.19 हे0 राजस्व वनभूमि कुल 1397.54 हे0 वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक अन्तर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा उपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा.लि. का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/142344/2021

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र कमांक 6–01/2024–एफसी दिनांक 02.02.2024

2. आपका पृष्ठां कमांक/एफ–1/845/2022/10–11/847 भोपाल दिनांक 06.02.2024

–000–

विषयांतर्गत के संबंध में वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत रकवा 1335.35 हे0 एवं राजस्व वन भूमि रकवा 62.19 हे0 कुल रकवा 1397.54 हे0 भूमि मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड का सिंगरौली जिला के सरई तहसील में आवंटित धिरौली कोल ब्लाक हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन प्रस्तावित है।

संदर्भित पत्र (2) से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक 6–01/2024–एफसी दिनांक 02.02.2024 में अधिरोपित बिन्दु कमांक iii, xv की जानकारी टेबुलर फार्म में तैयार कर अनुशंसा/अभिमत के साथ प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है।

उक्त बिन्दु कमांक iii, xv की जानकारी टेबुलर फार्म में तैयार कर अनुशंसा/अभिमत सहित संलग्न कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है। तथा आवेदक संस्थान से संबंधित बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त होने पर पृथक से प्रेषित किया जावेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ0 क्रमांक/तक0/2835 सिंगरौली, दिनांक 02.05.24

प्रतिलिपि – 1. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

SL No.	EDS Query	Reply
3	The proposed forest land is having density of forests ranging from 0.4 to 0.6 density wherein 5,70,666 no. of trees are estimated to be affected from the proposed activities. The detail of the forest crops and diameter classes of valuable trees estimated needs to be elaborated and phase wise felling details should also be indicated	The trees getting affected has to be felled in phase manner within a time span of 40 years from the start of the mining and during this period reclamation of mined out area and plantation of trees will be carried out. It is estimated that approximately 36,38,165 trees will be planted against the felling of estimated 5,70,666 trees. The species wise and diameter class wise details are already uploaded by DFO Singrauli in online Part-II wherein out of 5,70,666 trees marked for felling 1,48,526 trees are of less than 30 cm diameter and 72,991 trees are of more than 90 cm diameter. In the proposed forest land, there are many compartments where density is even less than 0.4 to 0.6 Compartment wise density report is :-

Range	Compartment No.	Density
Waidhan	354, 356, 353	0.5
Waidhan	361	0.3-0.5
Sarai East	377	0.2-0.4
Sarai East	363, 373, 359	0.3-0.5
Sarai East	337, 371, 372, 362, 360, 357	0.2-0.5
Sarai East	364	0.4-0.5
Sarai East	370	0.4-0.6

Further the table given below explains the phase wise felling of trees and tentative number of trees to be planted.

Phasing of Land	Years from start of mining Operation	Land Requirement (ha.) Forest Land	Land Requirement (ha.) Tentative no of tree to be felled	Plantation on Reclaimed Land (Ha.) Plantation area in forest Land (ha.)	Plantation on Reclaimed Land (Ha.) Plantation area in Non Forest Land (ha.)	Plantation on Reclaimed Land (Ha.) Total Plantation area	Number of Tree Planted Plantation in forest land (Nos)	Number of Tree Planted Plantation in non-forest land (Nos)	Number of Tree Planted Total Plantation (Nos)
Phase I	1 to 3	345.33	141011	4	16	20	10000	40000	50000
Phase II	4 to 5	300.17	122570	32	8	40	48000	12000	60000
Phase III	6 to 10	237.06	96800	224	259.57	483.57	336000	389355	725355
Phase IV	11 to 15	136.17	55603	150	76.94	226.94	225000	115410	340410
Phase V	16 to 20	220.41	90001	150	74.77	224.77	225000	112155	337155
Phase VI	21 to 30	108.66	44370	200	123.62	323.62	300000	185430	485430
Phase VII	31 to 40	49.74	20311	200	210.45	410.45	300000	315675	615675
Final Closure		0	0	437.54	245.22	682.76	656310	367830	1024140
Total		1397.54	570666	1397.54	1014.57	2412.11	2100310	1537855	3638165

The Plantation will be taken up as part of reclamation activity, during the life of mine. This is over and above the CA plantation area 1000plant/ha. Over 1400 ha. CA area in non-forest land.

SL No.	EDS Query	Reply
15	As per the 3-D subsidence prediction study report Maximum tensile strain reported in the proposed area is 17.47. The state shall examine the same and submit its comments in case the proposal is for underground mining only.	DFO office is not competent to comment on Subsidence report or tensile strain. However UA has submitted Subsidence report in Parivesh portal. And this proposed coal block is not for Underground mining only.

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

पुराना जिला पंचायत के पास मे
ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

आवश्यक/अविलम्ब

क्र0/तक0/ 3016 सिंगरौली, दिनांक.. 11-05-2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल

विषय:– वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न, माड़ा एवं पूर्व सरई के विभिन्न आर.एफ. वन कक्षों के रकबा 1335.35 हे0 वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकबा 62.19 हे0 राजस्व वनभूमि कुल 1397.54 हे0 वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक अन्तर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा उपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा.लि. का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/142344/2021

संदर्भ:– 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6–01/2024–एफसी दिनांक 02.02.2024
2. आपका पृष्ठां कमांक/एफ–1/845/2022/10–11/847 भोपाल दिनांक 06.02.2024
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड का प्राप्त पत्र दिनांक 11.05.2024

–000–

विषयांतर्गत के संबंध में वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत रकवा 1335.35 हे0 एवं राजस्व वन भूमि रकवा 62.19 हे0 कुल रकवा 1397.54 हे0 भूमि मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड को सिंगरौली जिला में आवंटित धिरौली कोल ब्लाक हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन प्रस्तावित है।

संदर्भित पत्र (2) से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक 6–01/2024–एफसी दिनांक 02.02.2024 में अधिरोपित बिन्दु कमांक i, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, एवं xiv की जानकारी आवेदक संस्थान से टेबुलर फार्म में तैयार करने हेतु लेख किया गया है।

सन्दर्भित पत्र (3) से उक्त बिन्दुओं की जानकारी आवेदक संस्थान से टेबुलर फार्म में प्राप्त कर मूलतः संलग्न कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ0 क्रमांक/तक0/ 3017 सिंगरौली, दिनांक. 11-05-2024

प्रतिलिपि – 1. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली
11/5/2024

Sl. No.	EDS Query	Reply
3	The proposed forest land is having density of forests ranging from 0.4 to 0.6 density wherein 5,70,666 no. of trees are estimated to be affected from the proposed activities The detail of the forest crops and diameter classes of valuable trees estimated needs to be elaborated and phase wise felling details should also be indicated	The trees getting affected has to be felled in phase manner within a time span of 40 years from the start of the mining and during this period reclamation of mined out area and plantation of trees will be carried out. It is estimated that approximately 36,38,165 trees will be planted against the felling of estimated 5,70,666 trees. The species wise and diameter class wise details are already uploaded by DFO Singrauli in online Part-II wherein out of 5,70,666 trees marked for felling 1,48,526 trees are of less than 30 cm diameter and 72,991 trees are of more than 90 cm diameter. In the proposed forest land, there are many compartments where density is even less than 0.4 to 0.6 Compartment wise density report is :-

Range	Compartment No.	Density
Waidhan	354, 356, 353	0.5
Waidhan	361	0.3-0.5
Sarai East	377	0.2-0.4
Sarai East	363, 373, 359	0.3-0.5
Sarai East	337, 371, 372, 362, 360,	0.2-0.5
Sarai East	364	0.4-0.5
Sarai East	370	0.4-0.6

Further the table given below explains the phase wise felling of trees and tentative number of trees to be planted.

		Land		Plantation on			Number of Tree Planted		
Phasing of Land	Years from start of mining Operation	Forest Land	Tentative no of tree to be felled	Plantation area in forest Land (ha.)	Plantation area in Non Forest Land (ha.)	Total Plantation area	Plantation in forest land (Nos)	Plantation in non-forest land (Nos)	Total Plantation (Nos)
Phase I	1 to 3	345.33	141011	4	16	20	10000	40000	50000
Phase II	4 to 5	300.17	122570	32	8	40	48000	12000	60000
Phase III	6 to 10	237.06	96800	224	259.57	483.57	336000	389355	725355
Phase IV	11 to 15	136.17	55603	150	76.94	226.94	225000	115410	340410
Phase V	16 to 20	220.41	90001	150	74.77	224.77	225000	112155	337155
Phase VI	21 to 30	108.66	44370	200	123.62	323.62	300000	185430	485430
Phase VII	31 to 40	49.74	20311	200	210.45	410.45	300000	315675	615675
Final Closure		0	0	437.54	245.22	682.76	656310	367830	1024140
Total		**1397.54**	**570666**	**1397.54**	**1014.57**	**2412.11**	**2100310**	**1537855**	**3638165**

The Plantation will be taken up as part of reclamation activity, during the life of mine. This is over and above the CA plantation area 1000plant/ha. Over 1400 ha. CA area in non-forest land.

Sl. No.	EDS Query	Reply
15	As per the 3-D subsidence prediction study report Maximum tensile strain reported in the proposed area is 17.47. The state shall examine the same and submit its comments in case the proposal is for underground mining only.	DFO office is not competent to comment on Subsidence report or tensile strain. However UA has submitted Subsidence report in Parivesh portal. And this proposed coal block is not for Underground mining only.

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

Stratatech Mineral Resources Private Limited

क्रमांक : एस.एम.आर.पी.एल. / 2024 / 203 दिनांक : 11.05.2024

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, सिंगरौली
जिला– सिंगरौली (म0प्र0)

विषयः– **वन मंडल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न, माड़ा एवं पूर्व सरई के विभिन्न RF वन कक्षों के रकबा 1335.35 हे0 वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकबा 62.19 हे0 राजस्व वन भूमि कुल 1397.54 हे0 वनभूमि में धिरौली कोल ब्लाक अन्तगर्त ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा उपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि. का आनॅलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/142344/2021।**

संदर्भः– 1. Letter of Government of India, Ministry of Enviornment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), New Delhi Dated 02.02.2024.
2. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–1 / 845 / 2022 / 10–11 भोपाल दिनांक 06.02.2024।

विषयांतगर्त उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में जारी EDS का प्रतिउत्तर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है एवं उपरोक्त EDS का प्रतिउत्तर टेबुलर फार्म में तैयार कर आवश्यक दस्तावेजो सहित दो प्रतियों में आपके समक्ष प्रस्तुत है।

धन्यवाद!

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्राधिकृत अधिकारी
स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड

Stratatech Mineral Resources Private Limited
Adani Corporate House, Shantigram,
S G Highway Ahmedabad 382 421
Gujarat, India
CIN: U14290GJ2019PTC110138

Tel +91 124 255 5555
Fax +91 79 2555 5500
Info@adani.com
www. adanienterprises.com

Regd Office: "Adani Corporate House", Shantigram, Nr.Vaishnodevi, S. G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad - 382421

Reply from SMRPL to DFO Singrauli regarding the EDS raised for Dhirauli Coal Block

<table>
<tr><th>Sl.No</th><th>EDS Query</th><th>Reply</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Calculated area of Shape file/ KML file of Forest land proposed for diversion within the mining lease is found 1601.058 Ha (software calculated). However, instant proposal has been submitted for diversion of 1397.54 ha forest land only.</td><td>The total mining lease area of this project is 2672 Ha, out of which 1397.54 Ha is Forest land and 1274.46 Ha is non-forest land.
Modified KML file has been uploaded in Form-A (Part-1) of this proposal.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>The method of mining has been reported in the online application as Opencast + Underground. However, the State Govt. in their reference letter has mentioned the same as open cast method of mining. The state govt shall therefore examine the same and report whether the proposal is for underground mining, open cast mining or both. The detail of area proposed for OCP and underground mining including the component wise KML file shall be submitted</td><td>In Singrauli district, there are more than 15 mines. All these mines are Open cast mines. Some of these mines are working even more than 200m deep Like- Dudhichua OCP Expansion (Max. depth of working 310m), Nigahi Expansion OCP (Max depth of working 300m) Bandha Coal block (Proposed Max. depth of working 230m), Suliyari Coal mine (Max depth of working 240m.).
The Mining plan has been approved by Ministry of Coal vide letter dated 04.05.2021 for Dhirauli Coal Block. The Coal block is combination for O/C and UG both, Underground mining is overlapping below the Opencast mining.
Details of seams considered by mining method is as below.
<table>
<tr><th>Seam</th><th colspan="2">Extractable Reserves (MT)</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Seam</th><th colspan="2">Extractable Reserves (MT)</th></tr>
<tr><th>UG</th><th>OC</th></tr>
<tr><td>VIII-Top</td><td>-</td><td>4.76</td></tr>
<tr><td>VIII-Comb.</td><td>-</td><td>63.46</td></tr>
<tr><td>VII-Top</td><td>-</td><td>21.72</td></tr>
<tr><td>VII-Bott.</td><td>-</td><td>2.58</td></tr>
<tr><td>VII-Comb.</td><td>-</td><td>93.53</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Sl.No</th><th>EDS Query</th><th>Reply</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>VI</td><td>6.56</td><td>-</td></tr>
<tr><td>IV</td><td>35.08</td><td>-</td></tr>
<tr><td>III-Top</td><td>63.92</td><td>-</td></tr>
<tr><td>II</td><td>6.51</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>112.07</td><td>186.06</td></tr>
</table>

Out of total Extractable reserve (298.13 MT), 62.4% (186.06 MT) is extractable by Open cast method only and remaining 37.6% (112.07 MT) will be extracted by Underground method.

The total lease area of opencast mining is inclusive of underground mining and requires no additional land on account of underground, separately.
The component wise KML file is uploaded in Parivesh portal .</td></tr>
<tr><td>5</td><td>As per DSS analysis the proposed area is falling in Inviolate or In High conservation zone value (HCV) with majority area falling in Very Dense Forest category. The state shall submit the justification for proposing such pristine area 8-01/2024-FC I/64348/2024 for mining. Further, keeping in view the conservation value of the area, the state shall intimate whether any impact assessment/biodiversity study taking into account the impact of mining has been carried out or not. If so the details be provided.</td><td>The Ministry of Coal, Govt of India vide Order number NA-104/7/2020-NA on dated 03.03.2021 allotted the Dhirauli Coal Block to M/s Stratatech Mineral Resources Pvt Limited through auction. Out of 1397.54 Ha forest land required for this project, an area of 1172.14 Ha is coal bearing area and it is a site-specific project, where location of the project can't be changed.

Also, the proposed area lies in the Singrauli Coalfield which forms the northern most part of Son Mahanadi basin and occupies a prominent position on power map of India due to its vast Quarriable coal resources. Therefore, no alternative is available except the proposed land.

The plantation will be taken up as a part of reclamation activity over the non-forest land within the total mining lease area and same will be maintained as a green cover till the mining is carried out over forest land in order to mitigate the ecological loss and this is over and above the CA carried out in the instant proposal.</td></tr>
</table>

Sl.No	EDS Query	Reply
		With evolved concern on sustainability and as a sustainable miner, PP has conducted following studies like: • Carrying Capacity, • Ecosystem studies, • Carbon sequestration • Social Impact Assessment, • Cumulative impact assessment, • Subsidence study, • Wildlife Conservation, • Pond de-siltation study, • Hydrology and Hydrogeology study in the area to assess its impact with mitigative measures. PP has prepared a robust plan under EMP/EIA (Copy enclosed) to address environmental and ecological concerns as well as to restore the forest (under JFM) as renewable resources concurrently with progress of extraction of the non-renewable mineral therein, in a sustainable manner. We have additionally studied the potential of carbon sequestration in Dhirauli area due to afforestation, eco-restoration to be conducted those estimates to be creating a positive carbon sequestration capability in the arena during the entire span of mining.

<table>
<tr><th>Sl.No</th><th>EDS Query</th><th>Reply</th></tr>
<tr><td>6</td><td>Satellite imagery and Land use plan submitted by the user agency reveals that there are five (5) transmission lines which are passing through the proposed forest land for diversion. The copy of approvals granted under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan), Adhiniyam, 1980 along with NoC from concerned agencies to shift the power lines from the proposed area have not been submitted. The state shall therefore submit the copy of approvals under Van (Sanrakshan Evam
Samvardhan), Adhiniyam, 1980 and the copies of NOC from the concerned agencies. The state shall also intimate whether any additional forest land would be required for the shifting of transmission lines or not along with details</td><td>Out of the five Transmission Lines (TL) passing through the Dhirauli Coal block, four Transmission Lines belong to PGCIL and one belong to MPPTCL.
A. <u>MPPTCL 132KV Transmission Line:</u>
MPPTCL 132KV line was first diverted in the year 1969. Now again it is to be diverted. Final approval for shifting the line has been granted by MoEFC&C on 22.01.2024 (FP/MP/TRANS/155291/2022; 21.372 Ha). The copy of the approval letter is enclosed.
B. <u>PGCIL Transmission Lines:</u>
<table>
<tr><th colspan="5">Details of FC Granted of the four existing PGCIL Lines</th></tr>
<tr><th>Sl. No</th><th>Description of Transmission Line</th><th>Area Diverted (Ha)</th><th>Proposal Number</th><th>Date of grant ot Stage-1/II from MoEF</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Diversion of 114.724 Ha of forest land for route alignment of 765 KV s/c Sasan-Satna CK in Favor of Power Grid Corporation Of India Ltd. in District Singrauli, Sidhi and Satna, Madhya Pradesh</td><td>114.724</td><td>FP/MP/TRANS/986/2011</td><td>Stage-II Granted: 26.10.2012</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Diversion of 128.553 Ha of forest land for construction of 765 KV S/C Singraulil-Sidhi-Satna Transmission line in favour of M/S Power Grid Corporation Of India Ltd, Madhya Pradesh.</td><td>128.553</td><td>FP/MP/TRANS/3214/2011</td><td>Stage-II Granted: 07.03.2013</td></tr>
<tr><td>3</td><td>765 KV DC Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line</td><td>241.0995</td><td>FP/MP/TRANS/17449/2016</td><td>Stage-II Granted: 18.09.2020</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Diversion of 204.356 ha of forest land in favour of M/s Power Grid Corporation Limited for construction of 765 KV</td><td>204.356</td><td>FP/MP/TRANS/2914/2013</td><td>Stage-II Granted: 31.12.2014</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Sl.No</th><th>EDS Query</th><th>Reply</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td><table><tr><td></td><td>Vindhyanchal Poling Station to Satna Circuit-II Transmission Line in Satna, Singrauli, Katni and Sahdol districts, Madhya Pradesh.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
For the PGCIL Lines, a feasibility study was conducted to identify new alignments for shifting (re-diversion) of the Transmission lines. In this regard, PGCIL wrote to Ministry of Coal, Ref letter: WRTS-II/ENGG/Stratatech Mineral Resources Pvt. Ltd/Diversion/607 dated 21.06.2021.The said letter is enclosed and uploaded as annexure of Form-A (Part-1) in Parivesh portal. The proposal for shifting (re-diversion) of the four existing lines of PGCIL is under process.

For shifting these Transmission lines outside of Dhirauli Coal Block, additional forest land may be required based on the feasibility study.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Presence of water bodies like Nala/ Tributary are also visible in the proposed forest land. The state shall submit the detail of mitigation measures in this regard along with the NoC/permission from the concerned department.</td><td>The project proponent has prepared "Hydrology Report" for management of Nala tributaries in & around Dhirauli Coal Block. The DPR has been approved by WRD vide Memo no. 2512/G/W/MP/1-48 of 22 dated 19.04.2022. PP has also obtained NOC for Nalla diversion from state WRD and copy of the NOC from WRD for Nalla diversion (Memo no. 2512/G/W/MP/1-48 of 22, dated 19.04.2022) is uploaded in parivesh portal as an annexure document.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>The proposal involves diversion of 1397.54 ha forest land out of which 225.4 ha has been proposed for external dumping and 6.3 ha has been earmarked for infrastructure which are non-site specific. The details of total overburden area in the proposal involving both forest as well as non forest land has not been submitted, which is required to be done. The state shall also explore the possibility of shifting of these components on non-forest land.</td><td><u>A.Justification for using 225.4 Ha Forest land for External Dump (OB):</u>

1. Dhirauli Coal block has been envisaged as combination of both, Opencast and Underground mine. Dhirauli coal block has very high stripping ratio (10.55 Cum/t) and to extract 186.06 Mt coal, 1963.55 MBCM OB shall have to be removed.
2. The OB dump area is in combination of Private, Govt and Forest Land available in the Dhirauli block.
3. The Proposed OB dump can accommodate 259 MBCM (13 %) OB, dump height has been planned 90–100 meter height from ground level which is maximum possible elevation on grounds of DGMS safety stipulations.</td></tr>
</table>

Sl.No	EDS Query	Reply
		4. 225.4 ha of land is an absolute requirement for external dumping because: The in-crop seam that need to be touched to develop a working face is at 60 meters depth from surface. To touch it and cut a trench (longitudinally) because of hilly terrain has a compelling initial stripping ratio of 9:1 (Cum/t) 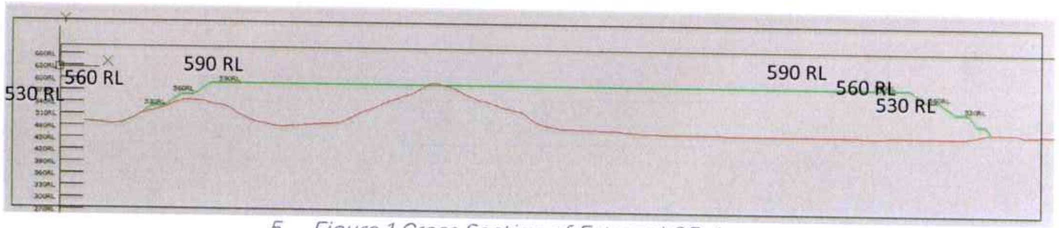 5. *Figure 1 Cross Section of External OB dump* 6. Internal dump can accommodate 1704.54 MBCM OB(87 %) which is planned by keeping 100 m lag distance from working bench of quarry with approx. 90 m height from the ground level, which has been best optimized on reasons of its safety and stability. 7. Forest land under proposed OB dump is coming between quarry and dump area (private Land) in linear extension surrounded by quarry and OB dump. During the mine operation, OB removed from quarry shall be accommodated in OB dump area and multiple accesses will be required. As the area is hilly forest, in order to make access road for initial mining operation and consequent dumping there of; most of the land will be affected by cut and fill activities, as an operational compulsion.

Sl.No	EDS Query	Reply
		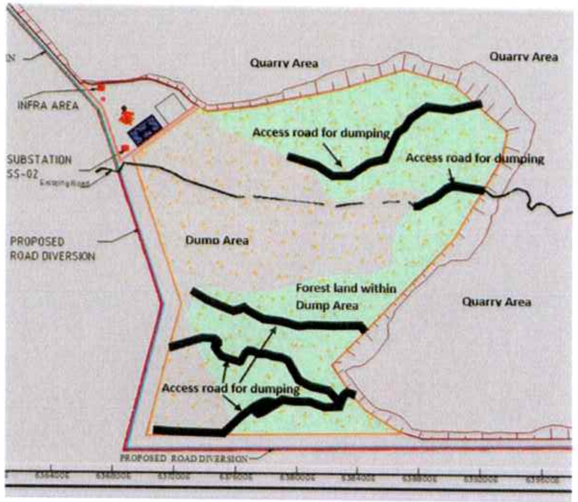 a. *Figure 2 Forest land in OB dump area and Quarry* 8. As explained above, due to location of forest land in proposed OB dump area it is inevitable to avert involvement of forest land that shall be taken in phases. 9. Any further optimization in working plan appears an impossibility, hence SMPRL as a responsible miner proposes detail scheme of afforestation as given in point 3 with huge carbon sequestration potential capability as detail in point 3. **B. Justification for using 6.3 Ha Forest land for Infrastructure.** 1. **We have now re-planned the infrastructure locations and all the infrastructure components will be in the non-forest land within the block boundary.**

<table>
<tr><th>Sl.No</th><th>EDS Query</th><th>Reply</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>C. The revised component wise breakdown of land is given below.
<table>
<tr><th rowspan="2">S No</th><th rowspan="2">Component Name</th><th colspan="2">Area inside (in Ha)</th><th rowspan="2">Total Area (Ha.)</th></tr>
<tr><th>Forest</th><th>Non-Forest</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Excavation Area</td><td>1068.51</td><td>1028.08</td><td>2096.59</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Safety Zone</td><td>10.46</td><td>9.27</td><td>19.73</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Green Belt Area</td><td>30.97</td><td>15.83</td><td>46.80</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Rationalization Area</td><td>51.82</td><td>20.29</td><td>72.11</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Infrastructure Area</td><td>0</td><td>30.05</td><td>30.05</td></tr>
<tr><td>6</td><td>OB Dump Area</td><td>225.4</td><td>162.15</td><td>387.55</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Other uses (Garland Drains)</td><td>2.75</td><td>2.59</td><td>5.34</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Other uses (Road Diversion)</td><td>2.56</td><td>1.57</td><td>4.13</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Other uses (Embankment)</td><td>5.07</td><td>2.43</td><td>7.50</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Other uses (Setting Pond)</td><td>0</td><td>2.20</td><td>2.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Area</td><td>1397.54</td><td>1274.46</td><td>2672.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9</td><td>As per the component wise breakup an area of 67.11 ha is designated as undisturbed area. The purpose and reason for including the same in the instant proposal has not been submitted</td><td>The appropriate term (as per mining plan) for the undisturbed area component is Rationalized area. These are scattered small patches inside the lease area. These scattered patches shall be used for access and plantation.
The total Rationalized area is 72.11 Ha. Out of 72.11 ha, forest land is 51.82 Ha and the balance area (20.29 Ha) will be in non-forest area.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Compensatory Afforestation has been proposed in total 45 patches comprising an area of 1397.523 ha wherein two CA patches</td><td>A. <u>Regarding CA patches in village Implipura (khasra no 2 & 19).</u>
1. DFO Shivpuri provided the site suitability certificate stating that based on ground report and forest compartment maps, the said khasras (no 2 & 19) are outside the forest compartment boundary.</td></tr>
</table>

Sl.No	EDS Query	Reply
	namely Village Imlipura, Khasra No 2 and 19, Shivpuri District are falling in the Forest compartment boundary as per DSS analysis. Moreover, these two patches are also located in Tiger corridor. The state shall examine the matter and ensure to provide NFL for CA as per guidelines. The CA sites namely Village - Dhandheda Kanad (Kh No 102,80,139,103), Village - Raipuriya (Kh No 78, 128 and 105) are located on the earthen dam, which may not be suitable for raising CA and the land may not be free from all encumbrances. Further, the documentary evidence of proposed CA site namely Village: Raghunathapura (Survey No. 3), Shivpuri District revealed that the ownership of land is with the Forest Department. The state shall examine the issues as above and ensure that all the CA areas are suitable, free from encumbrances and eligible for the purpose of CA as per prescribed guidelines.	2. District Collector Shivpuri also provided a letter stating that the said khasras are revenue land and a No Objection Letter (NOC) to transfer the land to Forest Dept. for CA purpose has been obtained. The NOC and Khasra P-II are enclosed and uploaded as annexure in Form-A (Part-1) **B. Regarding the CA sites in village Dhandheda Kanad (Kh No 102,80,139,103), Village - Raipuriya (Kh No 78, 128 and 105)** 3. DFO report indicates that the said CA patches in Dhandheda Kanad, and Rajpuriya are suitable for plantation and encroachment & encumbrance free. 4. In Rajpuriya village, in Khasra no 78, 128 and 105, for rainwater harvesting contour trenches, and small ponds were dug under PM Rojgar Yojana. 5. In Dhandheda Kanad, due to rainwater flowing, fissures in the form of gullies got created. There are NO artificial earthen dam constructed in the proposed patches. **C. Regarding CA land patch in village Village: Raghunathapura (Survey No. 3), Shivpuri District** 6. DFO Shivpuri got the area inspected by SDO Forest and Bairad Tehsildhar, and the said land is Not Forest owned land. In Forest maps the proposed CA area is outside the notified forest compartment 7. The said CA patches are encroachment and encumbrance free. 8. The Khasra P-II from 2009 to 2024 are enclosed and also uploaded in Form-A (Part-1) of Parivesh portal.
11	Mode of mineral/ coal transportation route and how the requirement of electricity and water will be met has not been given in the proposal. The state shall therefore submit the detailed mineral evacuation plan along with the details as to how the requirement of electricity and water would be met. The detail of additional forest land required for the purpose (if any) shall also be submitted.	**Coal Transportation Pathway:** 1. Coal that will be mined out from this block will be transported using the existing road of "*Suliyari-KhanuaKhas-Rajmilan*" To Gajra behra railway siding & also to Adani Power Plant (MEL) in Bandhaura. The KML and plan of the transportation route is attached with this letter. It is also proposed by Railway/Truck /Conveyor based on consumer location. The note on mineral (coal) transportation pathway is enclosed and uploaded in Parivesh portal. Also, a map showing coal transportation pathway is enclosed, and uploaded in the parivesh portal along with KML.

Sl.No	EDS Query	Reply
12	In accordance with the Para 7.8(i) of Chapter 7 of the consolidated guidelines and clarification issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Rules, 2023, the State govt shall give the justification for the necessity of opening the new mining lease along with details.	To meet the power demand of Country, Ministry of Coal has identified several coal blocks and auctioned them as commercial coal blocks and Dhirauli was one of them. SMRPL (Stratatech Mineral Resource Pvt Ltd) has been allotted the Dhirauli Coal block. SMRPL company is responsible Miner and deforestation, and afforestation is planned parallelly while trying to maintain eco-system balance
13	The Quantitative values on the parameters such as Cost of Human resettlement, Loss of public facilities has not be ascertained in the Cost-Benefit analysis, which is required to be done.	In the uploaded Cost-Benefit Analysis (CBA) report the Cost of human re-settlement in Forest land and loss of public facilities have been included in the Project Cost (Approved R&R Plan).
14	As per the SIR of the DFO, Singrauli Division, rights of 49 leaseholder have been recognized in the proposed area. The state shall submit details of the same and status of R&R plan.	49 leaseholders have been recognized in the Dhirauli Coal block and the cost of their Rehabilitation & Resettlement is included in R&R plan and the R&R plan is approved by Competent Authority. The details of 49 lease holders' details are uploaded in the Parivesh portal (Additional Information section, Sl.no 8 & 9).

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय,भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar, BHOPAL-462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक 6-एमपीआर 035/2022-बीएचओ/ दिनांक : ~~/01/2024.~~ 22/01/2024

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: **सिंगरौली जिले के अन्तर्गत वनमण्डल सिंगरौली में 132 के.व्ही. डोंगरीताल/ अनूपपुर-रजमिलान विद्धुत लाईन के विस्थापन कार्य** (due to Mining of Dhirauli Coal Block) हेतु 21.372 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत (online Proposal No. FP/MP/TRANS/155291/2022).

Sir,

I am directed to refer to the PCCF (LM), M.P. letter No. F-4/53/2022/10-11/4160 dated 07/12/2022 and 1593 dated 19/04/2023 wherein prior approval of Ministry of Environment, Forest and Climate Change for diversion of21.372 ha Reserved Forest land for laying of existing 132 KV DCDS Anuppur-Dongrital to Rajmilan Transmission Company Limited in Singarauli District of Madhya Pradesh was sought in accordance with Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. After due consideration of the proposal of the State Government, the 'in-principle' approval of the Central Government for diversion of the said forest land was accorded vide this office letter dated 24/05/2023 subject to fulfilment of certain conditions. The State Govt. of Madhya Pradesh vide their letter No. F-4/53/2022/10-11/4910 dated 02/11/2023 have furnished compliance report in respect of the relevant conditions stipulated in the in-principle approval for grant of final approval.

In this connection, on the basis of the compliance report under reference and confirmation of receipt of compensatory levies from National Authority of CAMPA online e.portal dated 01/08/2023, **final approval** of the Central Government under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 is hereby accorded for diversion of 21.372 ha Reserved Forest land for laying of existing 132 KV DCDS Anuppur-Dongrital to Rajmilan Transmission Company Limited in Singarauli District of Madhya Pradesh subject to following conditions and stipulations:-

(1) Legal status of the forest land diverted shall remain unchanged.

(2) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over **50.00 ha degraded-Forest land at Compartment No. RF-579, Gram Van Samiti-Ovari, Forest Range- Vargawan, Tehsil- Sarai, District- Singarauli** at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species shall be avoided.

(3) The State Government shall ensure that compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 has been completed in accordance with the relevant Rules and Guidelines issued by the MoEF&CC, GoI in this regard.

(4) User Agency shall restrict the felling of trees to the **enumerated 7056 numbers/ minimum number** in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the fellings.

(5) ***The State Govt will provide the details of number of trees actually felled during laying of the proposed transmission line, to the Regional Office, Bhopal for record purposes.***

(6) The User Agency shall comply with the guidelines for laying of transmission lines through forest as per Chapter 10 of FCA, 1980 Handbook, 2019.

(7) The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.

(8) The user agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter No. 7-25/2012-FC dated 05/-5/2014 & 19/11/2014.

(9) Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on the ground at the project cost, as per directions of the concerned DFO.

(10) Layout plan of the proposed diversion of the forest land shall not be changed without prior approval of the Central Government.

(11) No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

(12) No labour camp shall be established inside the forest land.

(13) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.

(14) The diverted forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

(15) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.

(16) The diverted forest land shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of the Central Government.

(17) All conditions of CWLW/SBWL/NBWL shall be strictly complied, wherever applicable.

(18) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

(19) ***All the conditions of In-principle approval dated 24/05/2023 shall be strictly complied.***

(20) Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

(21) Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests and wildlife.

2. As has been mentioned at Para-2 of the Stage-II approval, this approval for diversion of forest land is subject to fulfillment of the stipulated conditions mentioned in this approval letter. Therefore, in the event of non-compliance of any of the conditions laid out in this approval letter, the Regional Office of Ministry of Environment, Forest & Climate Change may withdraw the said approval for diversion of the forest land and stop all the non-forestry activities being carried out in the forest land besides initiating legal action as per provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980.

This has been issued with the approval of the Competent Authority.

24/1/24

(डॉ. योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी(वानिकी)

प्रतिलिपि :

1. वन महानिरीक्षक(एफसी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध)एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, तुलसीनगर, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश ।
4. कार्यपालन यंत्री, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (अ.उ.दा.नि) रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

24/1/24

(डॉ. योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी(वानिकी)

पावरग्रिड POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

CIN: L40101DL1989GOI038121

पश्चिम क्षेत्र पारेषण प्रणाली-II, क्षेत्रीय मुख्यालय / Western Region Transmission System – II, Regional Headquarters

Ref: WRTS-II/ENGG/Stratatech Mineral Resources Pvt. Ltd/Diversion/607 Date: 21.06.2021

To

The Nominated Authority,

Ministry of Coal, Government of India, Shashtri Bhavan, New Delhi-110 001

Sub: Diversion of existing Extra High Voltage (765kV) transmission lines of POWERGRID, passing through Dhirauli Coal Block Mines (M/S Stratatech Mineral Resources Private Limited): **Confirmation regarding identification of coal block mines and future coal block mines**

Ref: I) Letter dt. 28/12/2020 from Nominated Authority (Ministry of Coal) to Stratech Mineral Resources Private Limited;

ii) Letter ref. no. SMRPL/Dhirauli/2910121/01 dt. 29/01/2021 from Stratech to POWERGRID

iii) Letter ref. no. SMRPL/NA/MOC/09022021/1 dt. 09/02/21 from Stratech to Ministry of Coal

Respected Sir,

We would like to draw your kind attention towards the allocation of Dhirauli Coal block mines issued from Ministry of Coal vide letter dt. 28/12/20 **(Ann-1)** to M/s. STRATATECH Mineral Resources Private Limited (SMRPL). Further, vide letter dt. 09/02/21 **(Ann-2)**, M/s. Stratatech Mineral Resources Private Limited has requested to your good office towards grant of No Objection Certificate towards diversion of extra high voltage transmission lines passing through Dhirauli coal mines.

In this regard, preliminary survey to facilitate diversion of effected stretches of transmission lines of POWERGRID falling in DHIRAULI COAL BLOCK was carried out and the proposed new route alignments are as given under.

Sr. No.	Name of the Transmission line	Existing line section inside coal block.		Line length (Kms.) as per proposed diversion route (Approx.)	Remarks
		Tower locations (From... To...)	Length(kms.)		
1	765kV D/C Vindhyachal (VPS) – Jabalpur (PS) Ckt#3&4 Tr. Line	56 to 88	8.941	14.7 (diversion from tower no. 54 to 91)	Map showing the existing line alignment passing through Dhirauli coal block and proposed new route alignment is enclosed at **Ann-3**
2	765kV S/C Sasan – Satna Ckt#1 Tr. Line	73 to 102	10.554	16.88 KM – D/C line for both lines (diversion from tower no. 69 to 108 for Ckt#1 and 64 to 106 for Ckt#2)	
3	765kV S/C Sasan – Satna Ckt#2 Tr. Line	69 to 99	10.863		
4	765kV D/C Vindhyachal (VPS) – Satna Ckt#1&2 Tr. Line	57/59 to 83/85	9.777	15.2 Kms. (diversion from tower no. 54/56 to 92/94)	
TOTAL			**40.135 Kms.**	**46.78 Kms.**	

It is understood that CMPDI has identified potential reserves of coal blocks namely: - i) Mara II Mahan ii) Dhirauli, iii) Sulliyari, iv) Dongeri Tal-II, iv) Dongrital & v) Patpaharia (copy of the tentative respective coal block border marked in the topo sheet is appended herewith at **Ann-4**).

This is pertinent to mention that repeated diversion of these EHV transmission lines line due to coal block corridors, results in additional implications of forest involvement, cost towards diversions etc. Based on the confirmation of coal block corridor development plan details made available from CMPDI / Ministry of Coal, the diversion route alignments need to be reviewed to avoid repetitive diversion of transmission lines.

Considering above and in order to avoid repetitive diversion of EHV transmission lines line due to coal block corridors if any identified adjacent to Dhirauli coal block mines, we seek verification & confirmation of following from your end. :

a) Scrutiny of our proposed diversion route alignments to substantiate that these new route alignments are not passing through any other identified coal block corridors nearby. (The sketch & co-ordinates for diversion route alignments of POWERGRID transmission lines effected due to Dhirauli coal block, are enclosed herewith **Ann - 3A, 3B, 3C & 3D**)

b) If the above proposed diversion line alignments are passing through any coal block corridors identified / under allotment adjacent to Dhirauli coal block, confirmation of same with relevant details to our office.

This shall facilitate necessary reviewing of our proposed diversion line alignments to avoid coal blocks identified if any adjacent to Dhirauli coal block and thereby to minimize additional forest land requirements & cost implications towards diversion of power lines because of coal blocks.

Thanking you,

For POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED,

21/8/21

Utpal Sharma
Chief General Manager (Asset Management)
WRTS#2, Vadodara

Copy to: -

i) ED (WR2)
ii) ED (ESMD)
iii) ED (CMG)
iv) STA to Director (Projects)
v) STA to Director (Operations)

F. No. 8-62/2011-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(F.C. Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110003.
Dated: 26th October, 2012

To,

The Principal Secretary (Forests),
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.

Sub: Diversion of 114.724 ha. of forest land for route alignment of 765 KV S/c Sasan-Satna Ck-I in favour of Power Grid Corp. of India Ltd. in district Singrauli, Sindhi and Satna, Madhya Pradesh.

Sir,

I am directed to refer to the Government of Madhya Pradesh's letter No. F-4/11/29/2010/10-11/1588 dated 28.05.2011 on the above mentioned subject, wherein prior approval of the Central Government for the diversion of 114.724 ha. of forest land for route alignment of 765 KV S/c Sasan-Satna Ck-I in favour of Power Grid Corp. of India Ltd. in district Singrauli, Sindhi and Satna, Madhya Pradesh, was sought, in accordance with Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. After careful consideration of the proposal by the Forest Advisory Committee constituted under Section-3 of the said Act, Stage-I approval for the said proposal was granted vide this Ministry's letter of even number dated 10th July 2012 read with corrigendum of even number dated 30th August 2012, subject to fulfillment of certain conditions. The State Government has furnished compliance report in respect of the conditions stipulated in the stage-I approval and has requested the Central Government to grant final approval.

2. In this connection, I am directed to say that on the basis of the compliance report furnished by the Government of Madhya Pradesh vide letter No. F-4/11/29/2010/10-11/3200 dated 29.09.2012, No. F-4/11/29/2010/10-11/3393 dated 16.10.2012 and No. F-4/11/29/2010/10-11/3724 dated 23.10.2012 and User agency's letter No. CS/ ESMD/2012/1928 dated 26.10.2012, approval of the Central Government is hereby granted under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 114.724 ha. of forest land for route alignment of 765 KV S/c Sasan-Satna Ck-I in favour of Power Grid Corp. of India Ltd. in district Singrauli, Sindhi and Satna, Madhya Pradesh, subject to the following conditions:

(i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;

(ii) Compensatory afforestation over the degraded forest land double in extent to the area of diverted forest land shall be raised by the State Forest Department from funds realised from the user agency;

26/X/12

(iii) The State Government of Madhya Pradesh shall realize the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India and transfer the same to the ad-hoc CAMPA with intimation to this Ministry;

(iv) The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;

(v) To minimize the felling of for construction of transmission line, user agency shall comply with the following guidelines:

(a) Below each conductor, width clearance of 3 mts. would be permitted for taking the tension stringing equipment. The trees on such strips would have to be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.

(b) One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line;

(c) In the remaining width the right of way felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer whenever necessary to maintain the electrical clearance, trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum clearance, as may be stipulated by the Central Electricity Authority (CEA), between conductors and trees. The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above;

(d) User agency in consultation with the State Forest Department shall prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line, and provide funds for execution of the said scheme by the State Forest Department; and

(e) In case a portion of the transmission lines to be constructed is located in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees shall not be cut;

(vi) No labour camp shall be established on the forest land;

(vii) The User Agency shall identify the person(s) responsible for execution of project activities on non-forest land pending receipt of approval under the Act, and take credible action against them for violation of para 4.4 of the guidelines issued by this Ministry for implementation of the Forest (Conservation) Act, 1980. State Government shall also fix responsibility on concerned officials who failed to prevent the said violation;

(viii) The State-Government shall within six months submit a report on action taken by the User agency and the State Government against the persons responsible for violation of para 4.4 of the guidelines. In case of failure of the State Government to submit the said report within a period of six months and acceptance of the same by this Ministry, within

26/X/20/–

the next six months, the stage-II approval accorded for diversion of the said forest land shall automatically stand revoked

(ix) The User Agency shall provide alternate fuel to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the adjacent forest areas;

(x) The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;

(xi) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;

(xii) Any other condition that this Ministry and its Regional Office (Western Zone), Bhopal may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;

(xiii) User agency shall submit annual self-monitoring report, indicating status of compliance to the conditions stipulated in the approval, to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry; and

(xiv) The user agency and the State Government of Madhya Pradesh shall ensure compliance to provisions of the all relevant Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.

Yours faithfully,

Sd/-

(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
2. The Nodal Officer, Forest Department, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
3. The CCF (Central), Regional Office, Bhopal.
4. User Agency.
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi.
6. Guard File.

(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

F. No. 8-62/2012-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(F.C. Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110003.
Dated: 7th March , 2013

To,

The Principal Secretary (Forests),
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.

Sub: Diversion of 128.553 ha. of forest land for construction of 765 KV S/C Sasan-Satna Transmission Line **CKT-II** in district Singrauli, Sidhi and Satna in favour of Power Grid Corporation of India Ltd., Madhya Pradesh.

Sir,

I am directed to refer to the Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Land Management) and Nodal officer, Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Madhya Pradesh's letter No. F-4/11/30/2012/10-11/1860 dated 31.05.2012 on the above mentioned subject, wherein prior approval of the Central Government for the diversion of 128.553 ha. of forest land for construction of 765 KV S/C Sasan-Satna Transmission Line **CKT-II** in district Singrauli, Sidhi and Satna in favour of Power Grid Corporation of India Ltd., Madhya Pradesh, was sought, in accordance with section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. After careful consideration of the proposal by the Forest Advisory Committee constituted under Section-3 of the said Act, Stage-I approval for the said proposal was granted vide this Ministry's letter of even number dated 30th January 2013, subject to fulfilment of certain conditions. The State Government has furnished compliance report in respect of the conditions stipulated in the stage-I approval and has requested the Central Government to grant final approval.

2. In this connection, I am directed to say that on the basis of the compliance report furnished by the Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Land Management) and Nodal officer, Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Madhya Pradesh vide letter No. F-4/11/30/2012/10-11/632 dated 16.02.2013 and User Agency's letter No. CS/ ESMD/WR/ Sasan-II/ 2013 dated 04.03.2013, approval of the Central Government is hereby granted under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 128.553 ha. of forest land for construction of 765 KV S/C Sasan-Satna Transmission Line **CKT-II** in district Singrauli, Sidhi and Satna in favour of Power Grid Corporation of India Ltd., Madhya Pradesh, subject to the following conditions:

(i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;

(ii) Compensatory afforestation over the degraded forest land double in extent to the area of diverted forest land shall be raised by the State Forest Department from funds realised from the user agency;

(iii) The State Government of Madhya Pradesh shall realize the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India and transfer the same to the ad-hoc CAMPA with intimation to this Ministry;

7/3/2013

(iv) The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;

(v) To minimize the felling of for construction of transmission line, user agency shall comply with the following guidelines:

(a) Felling of trees shall be restricted to width clearance of 3 meters wide strip below each conductor for taking the tension stringing equipment. The trees to be felled shall be marked under supervision of forest staff. After stringing work is completed, the natural regeneration shall be allowed to come up;

(b) One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line;

(c) In the remaining width the right of way felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer whenever necessary to maintain the electrical clearance, trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum clearance, as may be stipulated by the Central Electricity Authority (CEA), between conductors and trees. The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above;

(d) User agency in consultation with the State Forest Department shall prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line, and provide funds within a period of thirty days from the date of issue of this letter, for execution of the said scheme by the State Forest Department. In case the user agency fails to prepare the scheme and deposit the amount required for its implementation, the State Government shall withdraw the land transfer order and the work shall be stopped;

(e) In case a portion of the transmission lines to be constructed is located in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees shall not be cut;

(vi) No labour camp shall be established on the forest land;

(vii) The State Government shall within a period of thirty days confirm the claim of the user agency regarding action taken by them against person(s) responsible for execution of project activities on non-forest land pending receipt of approval under the Act, and take credible action against them for violation of para 4.4 of the guidelines issued by this Ministry for implementation of the Forest (Conservation) Act, 1980. State Government shall within a period of thirty days also submit details of action taken by them against the concerned officials of the State Government who failed to prevent the said violation;

(viii) The user agency shall within a period of thirty days submit undertakings to comply with conditions stipulated at sl. No. 2 (i) and 2 (ii) in the in-principle approval for diversion of the said forest land accorded by this Ministry vide letter of even number dated 30.01.2013;

(ix) The State-Government shall within a period of one month submit report on action to be taken by then in para (v) (d), (vii) and (viii) above. In case of failure of the State Government to submit the said report within a period of one month and acceptance of the same by this Ministry, within the next one month, the stage-II approval accorded for diversion of the said forest land shall automatically stand revoked;

(x) The User Agency shall provide alternate fuel to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the adjacent forest areas;

(xi) The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;

(xii) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;

(xiii) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;

(xiv) Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;

(xv) Any other condition that this Ministry and its Regional Office (Western Zone), Bhopal may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;

(xvi) User agency shall submit annual self-monitoring report, indicating status of compliance to the conditions stipulated in the approval, to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry; and

(xvii) The user agency and the State Government of Madhya Pradesh shall ensure compliance to provisions of the all relevant Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.

Yours faithfully,

sd/-

(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-
1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
2. The Nodal Officer, Forest Department, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
3. The CCF (Central), Regional Office, Bhopal.
4. User Agency.
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi.
6. Guard File.

(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र
Regional Office, Western Region
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan"
लिंक रोड नं0–3, Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
Phone No. 0755-& 2466525, 2465496
फैक्स नं./Fax No. 0755-2463102
अणुडाक /E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

No. 6-MPA014/2017-BHO/ 844 **Date: 18/09/2020**

To,

The Principal Secretary (Forests)
Govt. of Madhya Pradesh,
Vallabh Bhawan
Bhopal.

Sub: Diversion of 241.0995 ha of Forest land for laying of 765 KV D/C Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling transmission line at Singrauli, Satna and Sidhi districts in favour of powergrid Corporation of India Ltd., Rewa.

Ref. 1) This office In-Principle approval letter No. 6-MPA014/2017-BHO/872 dated 20.11.2017.

2) Govt. of Madhya Pradesh letter No. F-4/41/2017/10-11/1189 dated 25.04.2019 and letter of even No. 2990 dated 08.09.2020.

3) Online transaction status of CA, NPV levies (vide e-portal) dated 26.02.2018, 22.02.2018, 16.02.2018 and 12.01.2018.

Sir,

I am directed to invite a reference to your letter No. F-4/41/2017/10-11/2936 dated 07.10.2017 on the above mentioned subject seeking prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980.

The Central Government vide letter (1) referred above had agreed In-principle for diversion of the above forest land for the purpose mentioned, subject to the fulfillment of all the conditions stipulated therein.

The State Government vide letter (2) referred above reported compliance on the fulfillment of the said conditions of the In-principle approval order.

Therefore, the undersigned is hereby directed to convey formal approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 241.0995 ha of Forest land for laying of 765 KV D/C Vindhyachal Pooling to Jabalpur Pooling transmission line at Singrauli, Satna and Sidhi districts in favour of powergrid Corporation of India Ltd., Rewa subject to the following terms and conditions:-

Specific Conditions:

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land shall be handed over only after required non-forest land for the project is handed by the user agency.
3. **Compensatory afforestation:**
    a) Compensatory Afforestation shall be taken up by the Forest Department over **482.256 ha degraded-forest land** at the cost of the User Agency.

Compensatory afforestation shall be of a mix of local indigenous species. Monoculture of any species shall be avoided. Details of CA is as per next page:

Sr. No.	Division	Circle	Compartment No.	Area in Ha.
1	Singrauli	East Sarai	RF-294	50.00
2		Karthua	RF 799	25.00
3		Karthua	RF 811	25.00
4		Mada	PF 548	50.00
5		Jiyawan	RF-804	40.00
6		Barka	PF-673	35.00
7		Sarai	PF-608	40.00
8		Jiyawan	RF-732	35.00
9	Sidhi	Churahat	P-1139	25.00
10			P-1141	25.00
11			P-1136	30.00
12			P-1137	24.00
13	Satna	Mukundpur	RF-730, 731 & 732	78.256
Total				**482.256**

b) Total No. of sapling to be planted shall be not less than 4,82,256 nos. (482.256 ha x 1,000) in CA land. The composition of saplings (number of species-wise) to be planted in the CA land shall be as per National Forest Policy and as per CA scheme submitted vide APCCF (LM), Govt. of MP letter No. F-4/41/2017/10-11/2936 dated 07.10.2017 and record shall be kept.

c) The standard size sapling (minimum height & minimum collar girth and maximum sturdiness quotient species wise) as approved by the State Govt. and as per specification in CA scheme submitted by APCCF (LM), Govt. of MP letter No. F-4/41/2017/10-11/2936 dated 07.10.2017 shall be planted in the selected CA land.

d) The height and collar girth (species wise) shall be measured & recorded at the time of plantation and in November of plantation year. Further, data of height, collar girth and survival percentage (species wise) twice a year (April & November month) shall be recorded & records shall be maintained.

e) The Sturdiness Quotient of the plants at the time of plantation shall not be more than 7.

$$\text{The Sturdiness Quotient} = \frac{\text{The height of plant (cm)}}{\text{The collar diameter (mm)}}$$

f) All the live stumps and pollards having girth at ground level ≤90 cm and having coppicing properties present in this CA area shall be dressed from the ground level and girthwise record shall be kept.

g) The CA plantation shall be taken place before end of 2021 monsoon.

241.0995 ha
PGCIL
8/9/20

4. User agency shall restrict the felling of trees up to **44207** numbers/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the State Forest Department.
5. The user agency shall comply to the conditions stipulated in the minutes of meeting of 46th National Board of Wildlife meeting dated 08.12.2017 and conditions stipulated in the clearance letter of CWLW, Forest Department, Govt. of Madhya Pradesh vide letter No. मा.चि./765 के.व्ही. वि.ला./13–4(16)/1102 dated 09.02.2018.
6. The user agency had deposited Rs. 14,90,88,135 for CA in another proposal of 114.724 hactrare.

General Conditions:

1. The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
2. The User Agency shall comply with the guidelines for laying underground electric lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014 and Chapter 10 of F(C) Act, 1980 Handbook 2019.
3. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
4. No labour camp shall be established on the forest land.
5. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
6. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
7. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
8. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
9. The State Government and user agency shall comply the provisions of the all Acts, Rules, Regulation, guidelines, NGT order & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
10. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
11. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstanced be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
12. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per MoEF&CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 and Para 1.21 of FCA Handbook, 2019.
13. All the conditions stipulated in Stage-I/In-principle approval shall be strictly complied.
14. The user agency shall adhere to all rules, regulations, guidelines & acts enforced by State Govt. and Central Govt. for the proposal.

241.0995ha
PGCL
18/9/20

15. The six monthly Compliance Report for all the conditions stipulated in this Stage-II approval every year on 1st January and 1st July shall be uploaded on e.portal by the State Govt and submitted to this office also.
16. Any other condition that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest and wildlife.
17. In case of non-compliance of any of the above conditions, the concerned Divisional Forest officer shall report through the State Govt. to this office as per procedure laid down in the clause 1.9 of guidelines issued under Forest (Conservation) Act, 1980 on 25.10.1992.

This has been issued with the approval of the Competent Authority.

18/9/20

(B. Abhay Bhaskar)
Asstt. Inspector General of Forests(C)

Copy to: -

1. The Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force, Forest Department, Satpura Bhawan, Bhopal, Madhya Pradesh.
2. The Addl. Director General of Forests (FC), Govt. of India, Ministry of Environment and Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi – 110003.
3. The APCCF (LM) and Nodal Officer, Forest Department, Satpura Bhawan, Bhopal, Madhya Pradesh.
4. The Divisional Forest Officer, Forest Division Sidhi, Satna, Singrauli, District-Singrauli, Satna, Sidhi, MP.
5. The Manager, Power Grid Corporation of India Ltd. Rewa, Madhya Pradesh.
6. Order file.

241.0995 ha
PGCIL

18/9/20

(B. Abhay Bhaskar)
Asstt. Inspector General of Forests(C)

F. No. 8-63/2013-FC
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi - 110003
Dated: 31st December, 2014

To,

The Principal Secretary (Forests),
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.

Sub: Diversion of 204.356 hectares of forest land in favour of M/s. Power Grid Corporation of India Limited for construction of 765 KV Vindhyachal Poling Station to Satna Circuit -I and Circuit-II Transmission line in Satna, Singrauli, Katni and Sahdol districts, Madhya Pradesh.

Sir,

I am directed to refer to the Addl. Principal Chief Conservator of Forests (land management) and Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Madhya Pradesh's letter No. F-4/ 11/ 37/ 2013/ 10-11/ Vidhyut/ 2543 dated 1st August 2013 on the above mentioned subject, wherein prior approval of the Central Government for the diversion of 204.356 hectares of forest land in favour of M/s. Power Grid Corporation of India Limited for construction of 765 KV Vindhyachal Poling Station to Satna Circuit -I and Circuit-II Transmission line in Satna, Singrauli, Katni and Sahdol districts, Madhya Pradesh, was sought, in accordance with section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. After careful consideration of the proposal by the Forest Advisory Committee constituted under Section-3 of the said Act, Stage-I approval for the said proposal was granted vide this Ministry's letter of even number dated 10th July 2014 and corrigendum of even number dated 31st December, 2014, subject to fulfillment of certain conditions. The State Government has furnished compliance report in respect of the conditions stipulated in the stage-I approval and has requested the Central Government to grant final approval.

2. In this connection, I am directed to say that on the basis of the compliance report furnished by the Addl. Principal Chief Conservator of Forests (Land Management) and the Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Madhya Pradesh vide letter No. F-4/11/37/2013/10-11/Vidhyut/2782 dated 20th October 2014 approval of the Central Government is hereby granted under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 204.356 hectares of forest land in favour of M/s. Power Grid Corporation of India Limited for construction of 765 KV Vindhyachal Poling Station to Satna Circuit -I and Circuit-II Transmission line in Satna, Singrauli, Katni and Sahdol districts, Madhya Pradesh, subject to the following conditions:-

(i) Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;

(ii) State Forest Department shall create and maintain from funds realised from the user agency compensatory afforestation over the degraded forest land double in extent to the forest land being diverted (*i.e.* 2 x 204.356 = 408.712 hectare of degraded forest land) shall be raised and maintained by the State Forest Department at the cost of the user agency;

(iii) The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department;

(iv) The State Government shall realize the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India and transfer the same to the Ad-hoc CAMPA under intimation to this Ministry;

(v) The user agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;

(vi) In case of transmission lines passing through elephant reserves/corridors, additional clearances of at least 6 m shall be provided over and above minimum clearance (as stipulated under Central Electricity Authority (Measures relating to safety & Electricity Supply) Regulations, 2010) above the ground from the lowest conductor of the transmission lines;

(vii) Sagging of conductors shall be regularly monitored so as to ensure that height of conductors in forest areas at any time is not less than the minimum height stipulated in guidelines issued under the FC Act;

(viii) No new road shall be constructed in the forest areas for transportation of materials and machines, *etc.*;

(ix) The user agency shall organize environment awareness programs to create awareness among the employees as well as residents of adjoining areas on the need for better environmental management and its safeguards;

(x) The user agency shall take adequate measures to prevent soil erosion in the area identified for erection of transmission towers;

(xi) To minimize the felling of for construction of transmission line, user agency shall comply with the following guidelines:

(a) Below each conductor, width clearance of 7 mts. would be permitted for taking the tension stringing equipment. The trees on such strips would have to be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.

(b) One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line;

(c) In the remaining width the right of way felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer whenever necessary to maintain the electrical clearance, trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum clearance, as may be stipulated by the Central Electricity Authority (CEA), between conductors and trees. The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above;

(d) State Forest Department shall create and maintain plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line from funds realised from the user agency;

(e) In case a portion of the transmission lines to be constructed is located in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees shall not be cut.

(xii) No labour camp shall be established on the forest land;

(xiii) The User Agency shall provide alternate fuel to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the adjacent forest areas;

(xiv) The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;

(xv) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;

(xvi) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;

(xvii) Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;

(xviii) User agency shall submit annual report on compliance to conditions stipulated in this approval to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry;

(xix) Any other condition that this Ministry and its Regional Office (Western Zone), Bhopal may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

Yours faithfully,

sd/-

(H.C. Chaudhary)
Director

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
2. The Nodal Officer, Forest Department, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
3. The Addl. Principal Chief Conservator of forests Central), Regional Office (Western Zone), Bhopal.
4. User Agency.
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi.
6. Guard File.

(H.C. Chaudhary)
Director

कार्यालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म०प्र०)

क्रमांक/2147/भू-अर्जन/22 सिंगरौली दिनांक 18/11/2022

प्रति,

कलस्टर हेड,
स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड
जिला सिंगरौली(म0प्र0)

विषय :- **मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरेल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल ब्लाक हेतु भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीती में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 17 के तहत अनुमोदित पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीती प्रेषित किये जाने बावत।**

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि सिंगरौली जिले में स्थापित स्ट्राटेक मिनरेल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड परियोजना को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक हेतु माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा अनुमोदित भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीती में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 17 के तहत जारी भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीती को संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न:- कमिश्नर महोदय द्वारा अनुमोदित पुर्नवास नीति

संयुक्त कलेक्टर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

T3

धिरौली कोल माइन परियोजना,

(मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड)

जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

के लिए

पुनर्वास एवं पुर्नव्यस्थापन नीति

धारा 11 अधिसूचना दिनांक 15/02/2022

पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति
धिरौली कोल माइन परियोजना

प्रस्तावना

मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले की तहसील सरई में स्थित धिरौली कोल ब्लॉक को कोयला मंत्रालय के पत्र क. NA-104/7/2020-NA दिनांक 03 मार्च 2021 के द्वारा **मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड** को धिरौली कोल ब्लॉक के लिए सफल बोलीदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

धिरौली कोल माइन परियोजना हेतु निजी भूमि के अर्जन के लिए भू–अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

धारा–4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना – दिनांक 02.06.2021
धारा–11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना – दिनांक 15.02.2022

सिंगरौली जिले में एपीएमडीसी सुलियरी कोल माइन परियोजना एवं टीएचडीसी अमिलिया कोल माइन परियोजना के लिए भी भू–अधिग्रहण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं दोनों परियोजनाओं के लिए कमशः वर्ष 2018 एवं 2019 में म0प्र0 की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में समाविष्ट प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये तैयार की गई पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति का अनुमोदन माननीय आयुक्त महोदय द्वारा किया गया है। अतः एपीएमडीसी की सुलियरी कोल माइन की पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति 2018 एवं टीएचडीसी की अमिलिया कोल माइन परियोजना के लिए अनुमोदित पुनर्वास नीति 2019–20 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये एवं विस्थापितों के प्रतिकर सुविधाओं में समानता लाने हेतु धिरौली कोल माइन परियोजना के लिए पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति तैयार की गई है, जो अनुमोदन के दिनांक से प्रभावशील हो जायेगी।

धिरौली कोल ब्लाक, **मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड** परियोजनान्तर्गत तहसील सरई के अतंर्गत परियोजना प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवयर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार ग्रामों की भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है ।

क.	तहसील	ग्राम का नाम	कुल निजी भूमि का अर्जित रकवा हे. में
1	सरई	आमडाड	5.17
2	सरई	सिरसवाह	0.62
3	सरई	बेलवार	11.60
4	सरई	बासीबेरदाह	147.67
5	सरई	अमरईखोह	43.056
कुल योग			208.116

उपरोक्तानुसार धिरौली कोल ब्लाक परियोजना (मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड) हेतु निजी भूमि अर्जन से प्रभावित / विस्थापित परिवारो का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित है।

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति

भाग–1

परिभाषाएँ–

01. कम्पनी–कम्पनी से तात्पर्य मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड धिरौली कोल माइन परियोजना जिला सिंगरौली से है।

02. प्रभावित क्षेत्र–प्रभावित क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे गॉव या बस्ती से है जिसमे परियोजना स्थापित करने के लिए निजी, शासकीय एवं वन भूमियो का चयन किया गया है, चाहे इन निजी भूमियों का अर्जन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानो के तहत किया गया हो या सीधे भूमि स्वामियों से क्रय किया गया हो, या शासन के द्वारा शासकीय भूमि आवंटित या वन भूमियों का व्यपवर्तन किया गया हो, किन्तु जो भू–भाग परियोजना से छोड़ा जा रहा है वह क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र नही माना जावेगा। जिसे राजस्व अभिलेख नक्शा एवं खसरा मे चिन्हित किया गया हो।

03. विस्थापित व्यक्ति – कोई व्यक्ति जो प्रभावित क्षेत्र में धारा 11 के अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 15.02.2022 के 03 वर्ष पूर्व से अपने गृहस्थ जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के साथ निवास करता हो, विस्थापित व्यक्ति कहलायेगा। किन्तु यदि कम्पनी द्वारा भूमिस्वामियों से सीधे भूमि क्रय की गई है तथा उस भूमि का भू–अर्जन नही किया गया है तो भूमि की रजिस्ट्री दिनांक को कटऑफ दिनांक माना जायेगा तथा उस परिवार के लिये परिवार की परिभाषा इस नीति के कण्डिका 4 (क) के अनुसार मान्य की जावेगी।

04. विस्थापित परिवार –

(क)–उपरोक्त (कण्डिका 3 मे) परिभाषित विस्थापित व्यक्तियों से बना परिवार जिसमे पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चे और परिवार के मुखिया पर आश्रित अन्य व्यक्ति उदाहरणार्थ–विधवा मॉं, विधवा बहन, अविवाहित बहन, अविवाहित पुत्री या वृद्ध माता–पिता शामिल है।

(ख)–विस्थापित परिवार के प्रत्येक बालिग पुत्र, अविवाहित पुत्री, अविवाहित बहन एवं भाई जो धारा 11 की दिनांक 15.02.2022 को बालिग (18 वर्ष या ऊपर) हो गया है वह पृथक परिवार के रूप मे माना जावेगा।

(ग)– परियोजना प्रभावित क्षेत्र के ऐसे अनाथ नाबालिग बच्चो (जिनके माता–पिता न हो) को पुनर्वास लाभ दिये जाने के लिये एक अलग यूनिट माना जावेगा।

05. भू–विस्थापित परिवार –

ऐसा भूमि स्वामी जिसकी निजी भूमि के अर्जन हेतु एवार्ड पारित किया गया हो या उनकी निजी भूमि परियोजना हेतु क्रय की गई हो, उसका परिवार भू–विस्थापित परिवार कहलायेगा, चाहे वह अर्जन क्षेत्र में निवास कर रहा हो या नही। वारिसाना नामान्तरण से बने दिनांक 15/02/2022 को बालिग भूमि स्वामियों को भी अलग भू–विस्थापित परिवार माना जायेगा।

06. प्रभावित व्यक्ति–

ऐसा व्यक्ति जो अर्जन क्षेत्र में स्थित भूमि पर धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 15.02.2022 के पूर्व 03 वर्ष से भूमि पर खेती कर रहा हो या अन्य उद्यमों द्वारा अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हो और उस ग्राम मे अस्थाई/स्थाई रूप से निवास करता हो।

07. प्रभावित परिवार–

उपर्युक्त (कण्डिका 06) में परिभाषित प्रभावित व्यक्तियों से बना परिवार जिसमे पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चे और परिवार के मुखिया पर आश्रित अन्य व्यक्ति उदाहरणार्थ–विधवा मॉं, परित्यक्ता ,विधवा बहन, अविवाहित बहन, अविवाहित पुत्री या वृद्ध माता–पिता शामिल है।

08. विस्थापन दिनांक – प्रत्येक विस्थापित परिवारों को रिहायसी मकान खाली कर अधिग्रहित/आवंटित/व्यपवर्तित भूमि का भौतिक आधिपत्य पूर्ण रूप से कम्पनी को सौंपने के दिनांक को विस्थापन दिनांक माना जायेगा।

09. परियोजना के प्रभावितो की श्रेणी–

(क)–ऐसे परिवार जो धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के पूर्व परियोजना प्रभावित क्षेत्र मे लगातार तीन वर्ष से खेती कर रहा हो किन्तु ग्राम मे स्थाई या अस्थाई रूप से निवास नही कर रहा हो और भू–अर्जन मे उसकी पूर्ण या आंशिक भूमि अधिग्रहीत कर ली गई हो।

(ख)–ऐसे परिवार जो धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से स्वयं के मकान या किराये के मकान मे स्थाई रूप से ग्राम मे निवास कर कोई लघुउद्योग, व्यापार, या कोई अन्य उद्यम कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हो।

(ग)–ऐसा कृषि श्रमिक जो भूमिहीन है, तथा धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से ग्राम मे निवास कर खेती से जुड़े हुए कार्य कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हो।

(घ)–ऐसे अकृषि श्रमिक जो भूमिहीन है, तथा धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से खेती से जुड़े हुए कार्य तो नही करते किन्तु उस ग्राम मे निवास कर कृषि से जुड़े हुए अन्य कार्य कर अपने परिवार का जीवन यापन करते हो।

(ड0)–ऐसे परिवार जो धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से ग्राम मे अस्थाई रूप से निवास कर कृषि कार्य तो नही करते किन्तु वनोपज द्वारा अपने परिवार का जीवन यापन करते हो।

10. **पुनर्वास अनुदान की शर्तें**–कण्डिका 09 मे वर्गीकृत प्रभावित परिवार, यदि उक्त मे से एक या एक से अधिक श्रेणी मे आते है तो उन्हें एक ही श्रेणी से प्रभावित मान कर पुनर्वास लाभ दिये जाने हेतु पात्र समझा जावेगा

11. **रिहायशी मकान** : रिहायशी मकान से तात्पर्य वैसे मकान से है जिसमे कोई परिवार या व्यक्ति स्थायी रूप से भूमि अर्जन की प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि 15.02.2022 के तीन वर्ष पूर्व से अपने गृहस्थ जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के साथ निवास करता हो।

भाग–2

(व्यक्तिगत लाभ)

01. पुनर्वास अनुदान–

पुनर्वास अनुदान के रूप प्रत्येक विस्थापित परिवार को (मकान खाली करने के उपरान्त) विस्थापन उपरान्त 300 कार्य दिवस की मध्य प्रदेश शासन द्वारा अवार्ड दिनांक को प्रचलित न्यूनतम कृषि मजदूरी (MAW) की दर से परिगणित राशि का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा।

02. (अ–1)–मकान/प्लाट का आवंटन – परियोजना से विस्थापित परिवार को 90X60 वर्गफुट का प्लाट पुनर्वास के लिए चयनित ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे दिया जावेगा, जिसमे कम्पनी के द्वारा मकान का निर्माण कराया जावेगा। यदि विस्थापित परिवार के द्वारा कम्पनी द्वारा निर्मित मकान नही लिया जाता है तो उसके एवज में मकान निर्माण के लिए 6.00 लाख रू0 कम्पनी द्वारा देय होगा। यदि कोई परिवार पुनर्वास कालोनी मे प्लाट नही लेना चाहता है तो उसे प्लाट के बदले 2.50 लाख की राशि का भुगतान किया जावेगा। यदि कोई विस्थापित परिवार प्लाट एवं मकान दोनो नही लेना चाहता है तो उसे प्लाट के बदले 2.50 लाख रू0 एवं मकान के बदले 6.00 लाख रू0, कुल मिलाकर 8.50 लाख रू0 देय होगा।

(अ–2)–कैटल शैड/छोटी दुकान हेतु अनुदान – पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो न्यूनतम 75,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(ब) प्लाट का स्वत्वाधिकार–पुनर्वास कालोनी में विस्थापितो को कंपनी के आवंटन पत्र के आधार पर संबंधित तहसीलदार द्वारा विहित प्रारूप पर पट्टा जारी किया जावेगा। जिस पर विस्थापित व्यक्ति को भूमिस्वामी के समस्त अधिकार प्राप्त होगें एवं तहसीलदार के द्वारा जारी पट्टे के आधार पर नामान्तरण किया जा सकेगा। पट्टेदार भूमिस्वामी को विधि अनुसार भूमि के अन्तरण का अधिकार होगा।

04. **विस्थापन कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च** – प्रत्येक विस्थापित परिवार को भवन सामग्री घरेलू सामान व परिवार तथा पशुओ के दुसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक मुश्त राशि रूपये 60,000.00/–(साठ हजार रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

05. **वृद्धावस्था पेंशन**–प्रत्येक विस्थापित महिला एवं पुरूष सदस्य जिसकी उम्र विस्थापन दिनांक को 60 वर्ष की हो चुकी है उन्हें प्रतिमाह 2000.00 (दो हजार) रू0 की दर से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान आजीवन अथवा धिरौली कोल ब्लॉक बन्द होने तक दिया जावेगा (यह राशि कृषक श्रमिकों के सूचकांक के हिसाब से प्रतिवर्ष अप्रैल माह में सूचकांकन किया जायेगा)।

06. **शिक्षा एवं छात्रवृत्ति**– परियोजना क्षेत्र से विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार के बच्चो के अध्ययन के लिये खेल के मैदान सहित सर्व सुविधा युक्त विद्यालय भवन का निर्माण कम्पनी द्वारा पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे कराया जावेगा। इस विद्यालय मे कक्षा नर्सरी से 10+2 स्तर तक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम(सीबीएसई बोर्ड एवं डी.पी.एस. स्टैंडर्ड या उसके समकक्ष) से अध्ययन हेतु विद्यालय संचालित किया जायेगा तथा अध्ययन करने वाले बच्चो को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी, एवं विस्थापित परिवार के अध्ययन करने वाले प्रत्येक बच्चे को पुस्तके, लेखन सामग्री, स्कूल यूनीफार्म की व्यवस्था कम्पनी द्वारा निःशुल्क की जावेगी। विद्यालय मे अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्सोहित करने के लिए कम्पनी द्वारा प्रतिमाह निम्नानुसार छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जावेगी–

कक्षा	बालक	बालिका
नर्सरी से 12 तक	700	900

10वीं एवं 12वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को 50,000 रू0 दिया जावेगा।

07. **चिकित्सा सुविधा**–

कंपनी के द्वारा पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे 20 बेड युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी) संचालित किया जावेगा जिसमें प्रसूति गृह, पैथोलाजी लैब, आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, बाह्य रोगी चिकित्सा कक्ष, औषधालय भण्डार, अभिलेखागार, कार्यालय एवं प्रतीक्षा गृह, पेय जल आदि का प्रावधान होगा। इस चिकित्सालय मे परियोजना से विस्थापित/प्रभावित परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

08. **महुआ एवं तेन्दू पत्ता संग्रहण भत्ता**–

प्रत्येक विस्थापित परिवार जो महुआ या तेन्दूपत्ता का संग्रहण करके अथवा अन्य वनोपज/वनाधिकार से अपने परिवार का जीवन यापन करता था, जिसकी पुष्टि वनविभाग द्वारा जारी किये गये समुचित दस्तावेजों से होती है उसे तो न्यूनतम 500 कार्य दिवसों की मध्य प्रदेश शासन द्वारा एवार्ड दिनांक को प्रचलित न्यूनतम कृषि मजदूरी दर से परिगणित राशि जो रू0 100000.00 (एक लाख) से कम नही होगी, एक मुश्त देय होगी।

09. विस्थापित परिवार को नौकरी, प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति–

क. प्रत्येक विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को परियोजना की आवश्यकता एवं योग्यतानुसार कम्पनी या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त एम.डी.ओ./संविदाकार में, रोजगार/नौकरी उपलब्ध कराने मे प्राथमिकता दी जावेगी। अशिक्षित विस्थापितों को परियोजना क्षेत्र मे हो रहे निर्माण कार्यों में अकुशल श्रमिक के रूप रोजगार उपब्लध कराये जाने मे प्राथमिकता दी जावेगी। परियोजना मे रोजगार के लिए विस्थापित व्यक्ति अपना नाम परियोजना प्रतिनिधियों के पास दर्ज करायेंगें। इस कार्य में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच का सहयोग अपेक्षित रहेगा। परियोजना प्रबंधक द्वारा समय–समय पर परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाये जावेगे ताकि परियोजना से विस्थापित परिवारों की कुशलता का विकास हो सके एवं उन्हे बेहतर रोजगार के अवसर एवं परियोजना में रोजगार मिल सके !

भू अर्जन के विरूद्ध रोजगार देने के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग तथा महिलाएं, जिनकी भूमि का अर्जन परियोजना हेतु किया जा रहा है तो ऐसे विस्थापित परिवार के सदस्यों में से परिवार के मुखिया द्वारा नामित व्यक्ति को रोजगार देने में प्राथमिकता दिया जायेगा। तथा इस संबंध में केन्द्र एवं राज्य में प्रचलित अधिनियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ख. रोजगार/नौकरी की व्याख्या–

रोजगार/नौकरी से तात्पर्य है कि कम्पनी के द्वारा किसी विस्थापित परिवार को परियोजना में या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त एम.डी.ओ./संविदाकार के माध्यम से सीधे नियुक्ति आदेश जारी करते हुए नियमित रूप से मासिक वेतन दिया जाकर नियमित कर्मचारियों की भॉती नियमित कटौती किया जाता है। यह नौकरी कम्पनी या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त एम.डी.ओ./संविदाकार के नियमानुसार होगा।

ग. यदि कम्पनी द्वारा विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी मे नही लिया जाता है या वह स्वयं नौकरी नही करना चाहता है तो उस परिवार के एक सदस्य को स्वरोजगार के लिए रू0 6.00 लाख (रू0 छः लाख) अनुदान राशि का एक मुश्त भुगतान या फिर 2800/– (यह राशि कृषक श्रमिकों के सूचकांक के हिसाब से प्रतिवर्ष अप्रैल माह में सूचकांकन किया जायेगा) प्रति माह वार्षिकी (Annuity) 20 वर्ष तक कम्पनी द्वारा दिया जायेगा।

घ. बेरोजगारी भत्ता–

परियोजना से विस्थापित हो रहे परिवारों में से हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को विस्थापन दिनांक से 03 वर्ष के अन्दर यदि कम्पनी द्वारा रोजगार नहीं दिया जाता है तो उस व्यक्ति को तत्कालिन प्रचलनशील न्यूनतम शासकीय कृषि मजदूरी दर (MAW) के मान से परिगणित राशि, जो कि रू0 7200/– प्रति माह से कम नहीं होगा, दिया जावेगा। यदि परिवार के मुखिया कोई महिला सदस्य है तो उसे भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। किन्तु यह बेरोजगारी भत्ता विस्थापन दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक देय होगा, बसर्ते उस परिवार के एक व्यस्क सदस्य को स्वरोजगार के लिए कम्पनी द्वारा रू0 6.00 लाख एक मुश्त राशि या 2800/– (यह राशि कृषक श्रमिकों के सूचकांक के हिसाब से प्रतिवर्ष अप्रैल में सूचकांकन किया जायेगा) प्रति माह वार्षिकी (Annuity) 20 वर्ष तक का शुरूआत नहीं किया गया हो।

ङ. रोजगार व नौकरी के विकल्पो का चयन –

यदि कोई विस्थापित व्यक्ति कंडिका घ में उल्लिखित रोजगार/नौकरी के एवज में बेरोजगारी भुगतान की शुरूआत पश्चात रोजगार/नौकरी के एवज में एक मुश्त देय राशि के विकल्प का चयन करता है तो वैसी स्थिति में कम्पनी द्वारा एक मुश्त राशि के भुगतान दिनांक तक भुगतान की गयी बेरोजगारी भत्ता की राशि को घटाकर शेष राशि प्रदान किया जावेगा।

च. **विस्थापितों को प्रशिक्षण**– कम्पनी के द्वारा अकुशल विस्थापितों के लिए निःशुल्क औद्योगिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आयोजित कराये जायेंगें, तथा प्रशिक्षित विस्थापितों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रशिक्षण के दौरान विस्थापित परिवार के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें एक सदस्य को 1000/– प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी।

10. स्वयं का रोजगार– कम्पनी के द्वारा विस्थापितों के अन्दर स्वयं का रोजगार स्थापित करने की क्षमता को विकशित करने के लिए कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण आयोजित कराये जायेंगें।

क. विस्थापित परिवार के सदस्यों को सहकारी समितियों के माध्यम से या व्यक्तिगत ठेके के माध्यम से कार्य मे लगाया जावेगा।

ख. कम्पनी के आवश्यतानुसार, विस्थापितों के द्वारा क्रय किये गये वाहनो को कम्पनी के कार्य मे लगाये जाने मे प्राथमिकता दी जावेगी।

ग. पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे निर्मित की गई दुकानो का आवंटन विस्थापित परिवारो को निःशुल्क किया जावेगा इनके लिए 90 प्रतिशत दुकानो का आरक्षण किया जावेगा। उक्त आरक्षण मुख्यतः किराना जनरल स्टोर, दवाई, दूध ब्रेड, लॉण्ड्री, सब्जी, फल आदि की दुकानो के लिए किया जावेगा। इन्ही दुकानो मे से एक दुकान उचित मूल्य की दुकान के लिए सुरक्षित रखी जावेगी। दुकान आवंटन का प्राथमिकता क्रम में निम्न वर्गों में आन्तरिक आरक्षण व्यवस्था अन्तर्गत लॉटरी निकाल कर किया जायेगा। उक्त आवंटन 03 वर्ष तक किया जायेगा। 03 वर्ष बाद पुनः आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। आवंटिती को स्वंय दुकान का संचालन करना पड़ेगा, अन्य को अन्तरित नहीं कर सकेगा। आवंटिती द्वारा दुकान के दुरूपयोग पर आवंटन निरस्त किया जायेगा। दुकान आवंटन का प्राथमिकता कम निम्नानुसार है :–

1. महिला द्वारा संचालित स्व–सहायता समूह (सभी वर्गो के लिए)।
2. शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति (सभी वर्गो के लिए)।
3. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति।
4. अनुसूचित जाति के व्यक्ति।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति।
6. महिला मुखिया से चलने वाले परिवार के सदस्य (सभी वर्गो के लिए)।
7. सामान्य वर्ग के व्यक्ति।

किन्तु यदि उक्त कमांक 01 से 07 तक निश्चित की गई श्रेणियों के आवंटन के लि पात्र कई व्यक्तियों के आवेदन पत्र दुकान प्राप्त करने के लिए लाये जाते है तो ऐसी स्थिति में दुकान की उपलब्धता के अनुसार लाटरी सिस्टम से उस वर्ग के व्यक्ति को दुकान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

11. श्रमकारी ठेका समितियों का गठन – श्रम ठेका समितियों का गठन परियोजना से विस्थापित परिवार के सदस्यों के द्वारा ही किया जावेगा। परियोजना की आवश्कतानुसार छोटे निर्माण अथवा अन्य कार्य कराये जाने में इन समितियों के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी। ऐसी स्व–रोजगार समिति एवं समूहो के गठन संबंधी समस्त कार्यवाही कम्पनी द्वारा की जावेगी। इन समितियों का पंजीकरण उप पंजीयक सहकारी समितियॉ के द्वारा कराया जायेगा।

जिला प्रशासन कम्पनी और पंजीकृत श्रम समिति के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया जावेगा, जिसके आधार पर ऐसी समिति को परियोजना मे कार्य दिया जा सकेंगा।

12. मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में छूट –

परियोजना से प्रभावित/विस्थापित व्यक्तियों द्वारा विस्थापन होने के पश्चात यदि कृषि भूमि खरीदी जाती है तो मध्य प्रदेश की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 की कंडिका (29.3) के तहत विस्थापित परिवारों को कृषि भूमि खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अधिग्रहण से प्रभावित क्षेत्रफल के बराबर क्रय की गई भूमि का मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क कम्पनी द्वारा देय होगा। इस कार्य से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किये गये मुआवजे का सही उपयोग किया जा सकेगा, और कृषि रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा।

भाग–3

पुनर्वास कालोनी एवं उसमें दी जाने वाली सुविधाएँ

01. विस्थापितो के लिए चयनित ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई में पुनर्वास हेतु तैयार किये गये भवनों के साथ जुड़ी हुई निम्नलिखित सुविधाएं विस्थापितों को उपलब्ध कराई जावेगी :–

(क) विद्यालय भवन– पुनर्वास कालोनी में विस्थापितो के बच्चो के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु सर्वसुविधा युक्त हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन का निर्माण कम्पनी द्वारा कराया जायेगा। इस विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को खेलने के लिए खेल के उपकरणों सहित खेल के मैदान की व्यवस्था की जायेगी। पुस्तकालय में हर वर्ष 50000/–रू0 (पचास हजार) फण्ड दिया जायेगा। जिसका उपयोग स्कूल के प्राचार्य द्वारा पुस्तक खरीदने मे किया जायेगा।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र– कंपनी के द्वारा पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे 20 बेड युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किया जावेगा जिसमें प्रसूति गृह, पैथोलाजी लैब, आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, बाह्य रोगी चिकित्सा कक्ष, औषधालय भण्डार, अभिलेखागार, कार्यालय एवं प्रतीक्षा गृह, पेय जल आदि का प्रावधान होगा। इस चिकित्सालय मे परियोजना से विस्थापित/प्रभावित परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

(ग) सामुदायिक भवन– पुनर्वास कालोनी के लिए एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जावेगा जिसमें एक हाल, एक कार्यालय कक्ष, एक पुस्तकालय एवं एक भण्डार गृह सम्मिलित होगा।

(घ) हाट बाजार परिसर– विस्थापितों के जीवन से जुड़ी आवश्यक सामग्रियों के प्रदायगी को सुलभ बनाने के लिए पुनर्वास कालोनी परिसर में साप्ताहिक बाजार लगाये जाने के लिए 5000 वर्गमीटर परिमाप की भूमि सुरक्षित रखी जावेगी। साप्ताहिक बाजार में लाइट, चबूतरा, टीनशेड, पानी पीने की व्यवस्था, पार्किंग की जगह रहेगी।

(ड0) सार्वजनिक खेल का मैदान– विस्थापितो के बच्चों को खेलने के लिए पुनर्वास कालोनी में खेल के मैदान के लिए 10,000 वर्गमीटर (01 हे0) के परिमाप मे भूमि सुरक्षित रखी जावेगी। खेल के मैदान का विकास एवं सुधार कम्पनी द्वारा किया जावेगा। शौचालय एवं आर0ओ0 प्लांट लगेगा। स्कूल मे खेलकूद हेतु 20,000 रू0 का फण्ड प्रति वर्ष दिया जावेगा।

(च) शुद्ध पेय जल व्यवस्था– विस्थापितो को पीने के लिए पानी की व्यवस्था हेतु ओवर हेड टैंक बनाकर पाइप लाईन से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जावेगी। यदि यह योजना सफल नही होती तो प्रत्येक 20 परिवार के लिए एक हैण्डपम्प लगाये जाने को प्राथमिकता दी जायेगी।

(छ) उचित मूल्य की दुकान– विस्थापितों को शासकीय दर पर खाद्यान्न सुलभ कराने हेतु एक उचितमूल्य की दुकान की स्थापना की जायेगी।

(ज) ऑगनवाड़ी केन्द्र– विस्थापित परिवारो के बच्चों, कुमारी कन्याओं एवं गर्भवती महिलाओं, के पोषण आहार की सुलभ व्यवस्था के लिए पुनर्वास कालोनी में ऑगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

(झ) मंदिर/मस्जिद/गिरिजाघर की स्थापना – पुनर्वास कालोनी मे विस्थापितों के धार्मिक अनुष्ठान, पूजन आदि की व्यवस्था के लिए आवष्यकतानुसार मंदिर/मस्जिद/ गिरिजा घर का निर्माण कराया जावेगा।

(ञ) सड़क– विस्थापितों के आवागमन की सुविधा के लिए पुनर्वास कालोनी को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 12 मीटर चौड़ी पक्की सड़क एवं कालोनी के अन्दर 09 मीटर चौड़ी पक्की सड़क का निर्माण कराया जावेगा।

(ट) सड़क विद्युत (स्ट्रीट लाईट)– विस्थापितों के प्रकाश युक्त आवागमन की सुविधा के लिए आन्तरिक एवं बाह्य सड़कों को विद्युत से प्रकाशित किया जायेगा।

(ठ) जल प्रभाव के लिए पक्की नालियाँ– विस्थापितों की कालोनी मे बने हुए आवासीय मकानों की जल निकासी के लिए सड़क के किनारे पक्की नालियों का निर्माण कराया जायेगा।

(ड) श्मसान/कब्रिस्तान परिसर– विस्थापितों के उपयोग हेतु कालोनी परिसर की बाह्य सीमा में विस्थापितों की सहमति के अनुसार श्मसान/कब्रिस्तान का निर्माण कराया जावेगा। जिसमें पानी की व्यवस्था एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कराया जायेगा।

नोट :– परियोजना द्वारा स्थापित पुनर्वास ग्राम की समस्त सुविधाएं तथा रोड पंचायत भवन इत्यादी ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगी।

(ढ) शौंचालयों की व्यवस्था– पुनर्वास कालोनी में विस्थापितों को आवंटित किये जाने वाले कम्पनी द्वारा निर्मित प्रत्येक मकानों में शौंचालयों की सुविधा का प्रावधान रखा गया है तथा सभी सार्वजनिक भवनों जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन, ऑगनवाड़ी, हाट बाजार परिसर इत्यादि में उचित संख्या में महिलाओं एवं पुरूषों के लिए पृथक–पृथक सामूहिक शौंचालयों का निर्माण कराया जायेगा।

02. **विशेष पैकेज**– परियोजना प्रभावित वह व्यक्ति जो परियोजना के अधिग्रहण क्षेत्र में धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के 03 वर्ष पूर्व से खेती करता चला आ रहा हैं, और उसकी निजी भूमि अर्जित कर ली गई है, किन्तु वह उस ग्राम मे मकान बनाकर आवाद नही है, जिसकी प्रमाणिकता वर्ष 2018–2019 के राजस्व अभिलेख से सिद्ध पाई जाती है, तो उन्हें भूमि की प्रतिकर राशि के अतिरिक्त निम्नानुसार विशेष पैकेज कम्पनी द्वारा दिया जावेगाः–

क– 0.01 से 0.99 हे0 भूमि पर	–	रू0 1500 प्रति परिवार प्रतिमाह।
ख– 1.00 हे0 से 1.99 हे0 भूमि पर	–	रू0 2000 प्रति परिवार प्रतिमाह।
ग– 2.00 हे0 से 3.99 हे0 भूमि पर	–	रू0 2500 प्रति परिवार प्रतिमाह।
घ– 4.00 हे0 से ऊपर	–	रू0 3000 प्रति परिवार प्रतिमाह।

उपरोक्त राशि प्रभावित परिवार के मुखिया को उसकी उम्र 50 वर्ष पूर्ण होने तक अथवा 20 वर्ष तक अथवा कम्पनी के बन्द होने तक जो भी पहले हो दिया जायेगा। किन्तु उपरोक्त विशेष लाभ उस परिवार को देय नही होगा जिसका कोई भी एक सदस्य परियोजना के रोजगार मे नियोजित हैं। विशेष पैकेज हेतु पात्र व्यक्ति के रकवे का निर्धारण अवार्ड में अंकित रकवे से किया जायेगा।

भाग–4

विवादो का निपटारा–

यदि किसी प्रकरण में विस्थापन की पात्रता के निर्धारण या विस्थापन से संबंधीत अन्य किसी मामले मे विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो प्रभावित व्यक्ति के द्वारा आवेदन करने पर कलेक्टर द्वारा निराकरण किया जावेगा जो दोनो पक्षों को मान्य होगा। कलेक्टर का आदेश अन्तिम एवं उभयपक्ष पर बाध्यकारी होगा।

राजीव रंजन मीना
कलेक्टर
जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

बच्चा प्रसाद
कलस्टर हेड
स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस
प्राईवेट लिमिटेड
जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector SINGRAULI

No. 4836 /FRA/TRIBAL/49/2022 SINGRAULI Dated. 31/03/2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCREN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) of the forest land 1335.35 Hectares and Revenue Forest land 100.84 Hectares proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1436.19 Hectares of forest/ Revenue Forest land proposed to be diverted in favour of Stratatech mineral Resources Private Limited for Coal Mine in Singrauli district falls within jurisdiction of Gram Panchayat- Jhalari, Majhaulipath, Dhirauli (Village – Amdand, Jhalari) (Amaraikhoh, Basiberdah, Belwar, Siraswah) (Dhirauli, Fatpani) in Singrauli district Compartment No RF 337, RF 353,RF 354, RF 356, RF 534, RF 361, RF 362, RF357, RF 360, RF 363, RF 364, RF 370, RF 371, RF 372, RF 373, RF 377

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1436.19 hectares of forest land purposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Village Forest Rights Committees(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan, Singrauli are enclosed as annexure I **01 T0 110** annexure II 01 T0 14.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any, having understood the purpose and the details for proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram sabha of Gram Panchayat- Jhalari, Majhaulipath, Dhirauli (Village – Amdand, Jhalari) (Amaraikhoh, Basiberdah, Belwar, Siraswah) (Dhirauli, Fatpani) in Singrauli district Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan, Singrauli & District level Forest Rights Committee, Singrauli and is enclosed as annexure 3 (1 to 58) to annexure 4. (1)

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when it was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha presence.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.As above.

31-3-22

Collector
Distt-Singrauli

9